RNI No. GUJHIN/2011/39228

गरवी गुजरात

GARVI GUJARAT

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 301
दि. 04.03.2026,
बुधवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

अहमदाबाद का 10×12 का 'ज़हर कक्ष': विदेशी सांपों से नशा, रेव पार्टियों तक फैला अंतरराज्यीय जाल

गुजरात में कानून-व्यवस्था को चुनौती देती एक चौंकाने वाली कार्रवाई में अहमदाबाद की अपराध शाखा और वन विभाग ने संयुक्त छापेमारी कर एक ऐसे संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसने 10×12 फीट के छोटे से कमरे को "ज़हर कक्ष" में बदल रखा था। नवरंगपुरा स्थित एक रिहायशी फ्लैट के भीतर 50 से अधिक विदेशी और अत्यंत जहरीले सांपों को ठूंस-ठूंस कर रखा गया था। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि इन सांपों का इस्तेमाल जहर निकालने, उसे ऊंची कीमत पर बेचने और कथित तौर पर हाई-प्रोफाइल रेव पार्टियों में नशे के रूप में सप्लाई करने के लिए किया जा रहा था। इस अवैध कारोबार में एक "डोज़" की कीमत 50,000 रुपये तक वसूली जाती थी।

छापेमारी के दौरान जो दृश्य सामने आया, उसने अधिकारियों को भी सन्न कर दिया। संकरे कमरे में प्लास्टिक बॉक्स, कांच के टेरारियम और अस्थायी कंटेनरों में अलग-अलग प्रजातियों के सांप रखे गए थे। पुलिस के अनुसार, शौकीन ग्राहकों के लिए "डसवाने" के अलग-अलग रेट तय थे—किस प्रजाति का सांप, कितनी मात्रा में विष, और किस तरीके से "सेशन" होगा। कुछ मामलों में सांप से सीधे कटवाया जाता था, तो कुछ में कथित तौर पर विष की बूंदें इंजेक्ट कराई जाती थीं। अधिकारियों का कहना है कि यह न केवल अवैध है, बल्कि जानलेवा भी है।

कार्रवाई में 41 वर्षीय मुख्य आरोपी मणिकनंदन नादर को गिरफ्तार किया गया है। मौके से बरामद सामग्री में केवल सांप ही नहीं, बल्कि कई दुर्लभ और विदेशी जानवर भी शामिल हैं—लाल हाथ वाला टैमरिन बंदर, अफ्रीकी ग्रे तोते, नीले-सुनहरे मैकाऊ तोते, फारसी बिल्लियां और नीदरलैंड के बौने खरगोश। वन अधिकारियों के मुताबिक, बरामद सांपों में कई प्रजातियां ऐसी हैं, जिनका भारत में आयात-निर्यात कड़े नियमों के तहत ही संभव है। प्रारंभिक आकलन के अनुसार, इन प्रजातियों को सीमा शुल्क से बचाकर अवैध तरीके से देश में लाया गया।

जांच एजेंसियों को आशंका है कि यह एक अंतरराज्यीय नेटवर्क है, जिसके

तार दक्षिण भारत के बंदरगाहों—संभवतः चेन्नई—से जुड़े हो सकते हैं। सीमा शुल्क विभाग अब यह खंगाल रहा है कि विदेशी प्रजातियां किस रास्ते और किन दस्तावेजों के सहारे देश में दाखिल हुईं। साथ ही, यह भी जांच हो रही है कि क्या किसी शिपिंग या लॉजिस्टिक चैनल का दुरुपयोग किया गया। सूत्रों का कहना है कि कुछ सांपों और उनके विष को कथित तौर पर दवा कंपनियों तक भी अवैध रूप से पहुंचाया गया, जबकि समानांतर रूप से जहर की सप्लाई ड्रग सिंडिकेट को की जा रही थी।

अधिकारियों के अनुसार, अहमदाबाद, गांधीनगर और खेड़ा जिलों में गुप्त रेव पार्टियों का एक सर्किट सक्रिय था, जहां "स्नेक वेनम एक्सपीरियंस" जैसी खतरनाक गतिविधियां आयोजित की जाती थीं। इस नेटवर्क में इवेंट मैनेजर, बिचौलिए और कथित रूप से कुछ हाई-प्रोफाइल ग्राहक शामिल हो सकते हैं। साइबर सेल ने आरोपी के मोबाइल फोन, लैपटॉप और बैंक खातों को खंगालना शुरू कर दिया है। डिजिटल चैट, क्रिप्टो ट्रांजैक्शन और पेमेंट गेटवे रिकॉर्ड से ग्राहकों की सूची तैयार की जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए कई एजेंसियां समानांतर जांच में जुटी हैं। वन विभाग वन्यजीव संरक्षण कानूनों के उल्लंघन की धाराओं के तहत कार्रवाई कर रहा है। सीमा शुल्क विभाग अवैध आयात-निर्यात के पहलुओं की जांच कर रहा है। वहीं, नगर निगम (AMC) घनी आबादी वाले इलाके में विदेशी जानवरों से संभावित जूनोटिक बीमारियों के खतरे का आकलन कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग को भी सतर्क किया गया है, क्योंकि विष के संपर्क से संक्रमण और एलर्जिक रिएक्शन का जोखिम बना रहता है।

विशेषज्ञों का कहना है कि सांप का विष अत्यंत शक्तिशाली जैव-रासायनिक तत्वों से बना होता है, जिसका चिकित्सा और शोध में सीमित एवं नियंत्रित उपयोग होता है। लेकिन अनियंत्रित और गैर-चिकित्सीय "डोज़" घातक साबित हो सकती है—दिल की धड़कन रुकना, तंत्रिका तंत्र का पक्षाघात, या गंभीर एलर्जिक शॉक जैसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं। पुलिस को आशंका है कि इस नेटवर्क के चलते पहले भी कुछ "अस्पष्ट" मेडिकल इमरजेंसी सामने आई होंगी, जिन्हें सामान्य ड्रग ओवरडोज़ समझकर दर्ज किया गया होगा। स्थानीय निवासियों ने बताया कि फ्लैट से कभी-कभी अजीब आवाजें और गंध आती थीं, लेकिन किसी ने संदेह नहीं किया कि भीतर इतना बड़ा अवैध कारोबार चल रहा है। पुलिस का मानना है कि आरोपी ने सुरक्षा के लिए सीमित लोगों को ही प्रवेश की अनुमति दी थी और अधिकांश सौदे डिजिटल माध्यम से तय होते थे। रेव पार्टियों के लोकेशन अंतिम समय पर साझा किए जाते थे, ताकि ट्रैकिंग से बचा जा सके। जांच अब इस बात पर भी केंद्रित है कि क्या इस गिरोह का अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन है। विदेशी प्रजातियों की उपलब्धता, उनकी कीमत और मांग को देखते हुए यह संभावना जताई जा रही है कि नेटवर्क सीमा पार के सप्लायरों से जुड़ा हो सकता है। प्रवर्तन एजेंसियां वित्तीय लेन-देन के जरिए मनी ट्रेल तलाश रही हैं, ताकि पूरे सिंडिकेट की परतें खुल सकें।

यह मामला केवल वन्यजीव तस्करी या ड्रग सप्लाई तक सीमित नहीं है, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और शहरी सुरक्षा का भी प्रश्न है। घनी आबादी वाले क्षेत्र में जहरीले सांपों का भंडारण किसी भी क्षण बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता था। अधिकारियों ने बरामद सभी जानवरों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया है और उनकी चिकित्सकीय जांच कराई जा रही है।

फिलहाल मुख्य आरोपी न्यायिक हिरासत में है और उससे पूछताछ जारी है। आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां संभव हैं। इस कार्रवाई ने स्पष्ट कर दिया है कि अपराधी किस हद तक मुनाफे के लिए खतरनाक रास्ते अपनाने को तैयार हैं। गुजरात में उजागर हुआ यह "ज़हर कक्ष" केवल एक कमरे का भंडाफोड़ नहीं, बल्कि उस अंधेरे नेटवर्क की झलक है, जो कानून, स्वास्थ्य और पर्यावरण—तीनों के लिए गंभीर खतरा बन चुका था।

लोकसभा की विशेषाधिकार समिति का गठन, रविशंकर प्रसाद को सौंपी गई कमान

नई दिल्ली। भारतीय संसदीय लोकतंत्र की कार्यप्रणाली में विशेषाधिकारों की व्यवस्था को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यही व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि सांसद बिना किसी बाहरी दबाव, भय या बाधा के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें। इसी क्रम में लोकसभा अध्यक्ष ने नई विशेषाधिकार समिति का गठन कर दिया है। वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री Ravi Shankar Prasad को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 15 सदस्यीय यह समिति 3 मार्च से प्रभावी हो चुकी है और अब सदन के विशेषाधिकार से जुड़े मामलों की जांच और समीक्षा की जिम्मेदारी संभालेगी। राजनीतिक दृष्टि से भी इस समिति का गठन ऐसे समय हुआ है जब संसद के भीतर बयानबाजी और आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज है।

समिति की संरचना पर नजर डालें तो इसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के अनुभवी सांसदों को शामिल किया गया है, ताकि निर्णय प्रक्रिया संतुलित और व्यापक दृष्टिकोण पर आधारित हो। कांग्रेस से Tariq Anwar और Manish Tewari को सदस्य बनाया गया है। तृणमूल कांग्रेस की ओर से Kalyan Banerjee को स्थान मिला है। भारतीय जनता पार्टी से Jagdambika Pal, Brig Mohan Agrawal, Ramvir Singh Bidhuri, Sangeeta Singh Deo और Trivendra Singh Rawat को शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त कांग्रेस के Manickam Tagore, डीएमके के T. R. Baalu और समाजवादी पार्टी के Dharmendra Yadav भी समिति का हिस्सा हैं। बहुदलीय प्रतिनिधित्व से यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि विशेषाधिकार मामलों की सुनवाई दलगत राजनीति से ऊपर उठकर की जाएगी।

विशेषाधिकार समिति का गठन ऐसे समय में हुआ है जब बजट सत्र के पहले चरण में इस मुद्दे को लेकर व्यापक चर्चा छिड़ गई थी। सरकार की ओर से संकेत दिया गया था कि नेता विपक्ष Rahul Gandhi के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस लाया जाएगा। विपक्ष ने तब सवाल उठाया था कि जब समिति का गठन ही नहीं हुआ है तो ऐसी प्रक्रिया आगे कैसे बढ़ेगी। इसी बीच भाजपा सांसद Nishikant Dubey ने राहुल गांधी के खिलाफ एक सबस्टेंटिव मोशन का नोटिस लोकसभा अध्यक्ष को सौंपा। इन घटनाक्रमों ने विशेषाधिकार समिति के गठन की आवश्यकता को और अधिक स्पष्ट कर दिया।

संसदीय परंपरा के अनुसार, यदि किसी सांसद को लगता है कि उसके विशेषाधिकारों का हनन हुआ है, या सदन की गरिमा को ठेस पहुंची है, तो मामला लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष उठाया जाता है। अध्यक्ष प्राथमिक परीक्षण के बाद उसे विशेषाधिकार समिति को संदर्भित कर सकते हैं। समिति संबंधित पक्षों को तलब कर सकती है, लिखित और मौखिक साक्ष्य ले सकती है तथा विस्तृत जांच के बाद अपनी रिपोर्ट सदन के पटल पर प्रस्तुत करती है। यदि दोष सिद्ध होता है तो समिति चेतावनी, फटकार, हिरासत या अन्य दंडात्मक कार्रवाई की सिफारिश कर सकती है। अंतिम निर्णय सदन के पास होता है।

भारतीय संविधान और संसदीय परंपराओं में विशेषाधिकारों की अवधारणा इस उद्देश्य से विकसित हुई है कि विधायिका स्वतंत्र और प्रभावी रूप से कार्य कर सके। सांसदों को सदन के भीतर कही गई बातों के लिए न्यायालय में उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता, ताकि वे निर्भीक होकर जनहित के मुद्दे उठा सकें। लेकिन इस स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी है। यदि कोई सदस्य या बाहरी व्यक्ति इस व्यवस्था का दुरुपयोग करता है या सदन की मर्यादा का उल्लंघन करता है, तो विशेषाधिकार समिति हस्तक्षेप करती है।

वर्तमान राजनीतिक माहौल में, जहां सार्वजनिक मंचों और सोशल मीडिया पर तीखी टिप्पणियां आम हो गई हैं, विशेषाधिकार समिति की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। कई बार संसद के भीतर दिए गए बयान या सदन से बाहर की गई टिप्पणियां विवाद का कारण बनती हैं। ऐसे में यह समिति एक संस्थागत तंत्र के रूप में काम करती है, जो तथ्यों की जांच कर संतुलित सिफारिश प्रस्तुत करती है। इससे संसद की गरिमा बनाए रखने में मदद मिलती है।

अध्यक्ष के रूप में रविशंकर प्रसाद का चयन भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कानून मंत्री के रूप में उनके अनुभव और विधिक पृष्ठभूमि को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि वे मामलों की सुनवाई में प्रक्रियात्मक शुचिता और विधिक संतुलन बनाए रखेंगे। संसदीय मामलों के जानकारों का मानना है कि समिति के समक्ष आने वाले मामलों की प्रकृति आने वाले समय में राजनीतिक विमर्श की दिशा तय कर सकती है। विशेषाधिकार समिति केवल दंडात्मक संस्था नहीं है, बल्कि यह संसद की आत्म-सुरक्षा की व्यवस्था है।

मुआवजे में देरी पर सख्त सुप्रीम कोर्ट: पेनल्टी की रकम नियोक्ता को खुद चुकानी होगी

नई दिल्ली। श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण और दूरगामी प्रभाव वाला फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम के तहत यदि किसी कर्मचारी या उसके परिजनों को मुआवजा देने में देरी होती है, तो उस देरी पर लगाई गई पेनल्टी की राशि बीमा कंपनी नहीं, बल्कि संबंधित नियोक्ता को अपनी जेब से चुकानी होगी। भले ही मूल मुआवजा बीमा पॉलिसी के तहत कवर क्यों न हो, लेकिन कानून द्वारा निर्धारित दंडात्मक राशि की जिम्मेदारी पूरी तरह नियोक्ता की ही रहेगी। इस फैसले को श्रमिक हितों की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जो यह संदेश देता है कि कर्मचारियों के अधिकारों के मामले में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

यह निर्णय जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस पी. बी. वराले की पीठ ने सुनाया। मामला न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की उस याचिका से जुड़ा था, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि मुआवजे में देरी पर लगाई गई पेनल्टी का भुगतान भी बीमा कंपनी को करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस व्याख्या को गलत ठहराते हुए स्पष्ट किया कि कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम की धारा 4ए(3)(बी) के तहत पेनल्टी की जिम्मेदारी सीधे तौर पर नियोक्ता पर ही डाली गई है और इसे बीमा कंपनी पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता।

अदालत ने अपने विस्तृत आदेश में कहा कि कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम एक सामाजिक कल्याणकारी कानून है, जिसे संसद ने श्रमिकों और उनके परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया है। ऐसे कानूनों की व्याख्या तकनीकी आधार पर नहीं, बल्कि उनके मूल उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उदारतापूर्वक की जानी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि जब कोई कर्मचारी कार्य के दौरान दुर्घटना का शिकार होता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार पर अचानक आर्थिक संकट टूट पड़ता है। ऐसे समय में त्वरित मुआवजा उनके लिए जीवन रेखा की तरह होता है। यदि नियोक्ता समय पर मुआवजा देने में विफल रहता है, तो उस पर दंड लगना स्वाभाविक और न्यायसंगत है।

पूरा मामला फरवरी 2017 की एक दुर्घटना से जुड़ा है। एक कर्मचारी की अपने नियोक्ता के वाहन को चलाते समय दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। मृतक के परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता की आवश्यकता थी, लेकिन उन्हें समय पर मुआवजा नहीं मिला। अंततः जुलाई 2017 में परिवार ने लेबर कमिश्नर के समक्ष याचिका दायर की। सुनवाई के बाद कमिश्नर ने मृतक के आश्रितों को 7.36 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया। इसके साथ ही 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज और देरी के लिए 35 प्रतिशत पेनल्टी भी निर्धारित की गई। वाहन का वैध बीमा होने के कारण मूल मुआवजा राशि बीमा कंपनी से वसूलने का आदेश दिया गया, लेकिन पेनल्टी नियोक्ता पर लगाई गई। बाद में यह मामला हाई कोर्ट पहुंचा, जहां यह कहा गया कि जब वाहन बीमित था और बीमा कंपनी जोखिम वहन कर रही थी, तो पेनल्टी की राशि भी बीमा कंपनी को ही चुकानी चाहिए। इसी आदेश के खिलाफ बीमा कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। शीर्ष अदालत ने मामले की गहन सुनवाई के बाद स्पष्ट किया कि बीमा अनुबंध केवल मुआवजे की राशि तक सीमित है। पेनल्टी, जो नियोक्ता की लापरवाही या देरी के कारण लगाई जाती है, उसे बीमा कंपनी पर थोपना कानून की मंशा के विपरीत होगा।

न्यायालय ने अपने फैसले में कई पूर्व निर्णयों का हवाला देते हुए दोहराया कि सामाजिक सुरक्षा से जुड़े कानूनों की व्याख्या कर्मचारियों के हित में की जानी चाहिए। अदालत ने कहा कि यदि पेनल्टी की जिम्मेदारी भी बीमा कंपनी पर डाल दी जाए, तो नियोक्ता समय पर भुगतान करने के प्रति उदासीन हो सकते हैं। इससे कानून का निवारक उद्देश्य कमजोर पड़ जाएगा। पेनल्टी का मूल उद्देश्य ही यह है कि नियोक्ता समय पर मुआवजा अदा करें और कर्मचारियों के अधिकारों के प्रति जिम्मेदार रहें।

इस फैसले के व्यापक प्रभाव भी सामने आएंगे। श्रम कानून विशेषज्ञों का मानना है कि अब नियोक्ताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि कार्यस्थल पर सुरक्षा मानकों का पालन हो और किसी दुर्घटना की स्थिति में मुआवजा तुरंत प्रदान किया जाए। देरी की स्थिति में उन्हें अतिरिक्त आर्थिक बोझ उठाना पड़ेगा, जिसे बीमा कंपनी के जरिए टाला नहीं जा सकेगा। इससे उद्योग जगत में जवाबदेही और अनुशासन बढ़ेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि बीमा कंपनियों की भूमिका जोखिम कवरेज तक सीमित है। वे नियोक्ता की व्यक्तिगत लापरवाही या कानूनन देरी के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराई जा सकतीं। अदालत ने कहा कि बीमा अनुबंध को इस प्रकार नहीं पढ़ा जा सकता कि वह नियोक्ता के सभी दायित्वों को स्वतः अपने ऊपर ले ले। पेनल्टी एक दंडात्मक प्रावधान है, जिसका उद्देश्य केवल क्षतिपूर्ति नहीं बल्कि जिम्मेदारी तय करना भी है।

यह निर्णय उन लाखों श्रमिक परिवारों के लिए राहत का संदेश है, जो दुर्घटनाओं के बाद लंबी कानूनी लड़ाई और आर्थिक तंगी का सामना करते हैं। अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि कानून की भावना श्रमिकों की सुरक्षा और सम्मान में निहित है। यदि नियोक्ता अपने दायित्वों से बचने की कोशिश करेंगे, तो उन्हें आर्थिक दंड भुगतना पड़ेगा।

कुल मिलाकर, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला न केवल एक कानूनी विवाद का समाधान है, बल्कि श्रमिक अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक सशक्त संदेश भी है। इससे यह सिद्ध होता है कि सामाजिक कल्याणकारी कानूनों की आत्मा को कमजोर करने की कोई भी कोशिश न्यायालय की कसौटी पर टिक नहीं सकती। अब नियोक्ताओं के लिए यह स्पष्ट संकेत है कि वे समयबद्ध और जिम्मेदार व्यवहार अपनाएं, अन्यथा देरी की कीमत उन्हें स्वयं चुकानी होगी।

आर्टिलरी क्षमता में बड़ा इजाफा: भारतीय सेना 300 स्वदेशी धनुष होवित्जर तोपों की खरीद को तैयार

नई दिल्ली। बदलते सुरक्षा परिदृश्य और सीमाओं पर बढ़ती चुनौतियों के बीच भारतीय सेना अपनी मारक क्षमता को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में निर्णायक कदम उठाने जा रही है। सेना जल्द ही 300 स्वदेशी 'धनुष' होवित्जर तोपों की खरीद का बड़ा ऑर्डर देने की तैयारी में है। रक्षा सूत्रों के अनुसार, इस प्रस्ताव को शीघ्र ही उच्चस्तरीय स्वीकृति मिल सकती है और इसके बाद औपचारिक प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इस नई खरीद के साथ सेना की आर्टिलरी ताकत में उल्लेखनीय वृद्धि होगी तथा 15 नई आर्टिलरी रेजिमेंट का गठन किया जाएगा, जिससे सीमावर्ती और संवेदनशील क्षेत्रों में तैनाती को मजबूती मिलेगी।

'धनुष' तोप भारत के स्वदेशी रक्षा उत्पादन प्रयासों का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। यह 155 मिमी, 45-कैलिबर की आधुनिक होवित्जर तोप है, जिसे 1980 के दशक में खरीदी गई Bofors howitzer तकनीक के आधार पर विकसित किया गया है। हालांकि मूल तकनीक विदेशी थी, लेकिन धनुष को भारतीय आवश्यकताओं के अनुरूप उन्नत किया गया है और इसका निर्माण देश की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों द्वारा किया जा रहा है। इस तोप में बाय-मॉड्यूलर चार्ज सिस्टम लगाया गया है, जिससे इसकी मारक क्षमता और फायरिंग दक्षता दोनों में सुधार हुआ है। लंबी दूरी तक सटीक प्रहार करने की इसकी क्षमता इसे आधुनिक युद्धक्षेत्र की जरूरतों के अनुरूप बनाती है।

इससे पहले भारतीय सेना 114 धनुष तोपों का ऑर्डर दे चुकी है। रक्षा अधिकारियों के अनुसार, इन तोपों की लगभग चार रेजिमेंट पहले ही सेना में शामिल की जा चुकी हैं, जबकि दो अन्य रेजिमेंट जल्द ही पूरी तरह परिचालन में लाई जाएंगी। अब प्रस्तावित 300 तोपों की नई खेप से कुल क्षमता में बड़ा विस्तार होगा। 15 नई आर्टिलरी रेजिमेंट बनने से सेना को पर्वतीय और मैदानी दोनों क्षेत्रों में सामरिक बढ़त मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि लंबी दूरी तक सटीक फायर सपोर्ट किसी भी जमीनी अभियान की सफलता का अहम आधार होता है, और धनुष इस भूमिका को मजबूती से निभा सकती है।

धनुष तोप ने जून 2018 में राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में सफल परीक्षण पूरे किए थे। कठोर मौसम और विविध परिस्थितियों में इसके प्रदर्शन का मूल्यांकन किया गया, जिसके बाद इसे सेना में शामिल किया गया। परीक्षणों के दौरान इसकी फायरिंग रेंज, सटीकता और स्थिरता को संतोषजनक पाया गया। इसके बाद से यह तोप क्रमिक रूप से विभिन्न इकाइयों में तैनात की जा रही है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि स्वदेशी उत्पादन होने के कारण रखरखाव, स्पेयर पार्ट्स और तकनीकी सहायता में आत्मनिर्भरता बढ़ती है, जो लंबी अवधि में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है।

सूचना

हमारे सभी पाठकों एवं शुभचिंतकों को सूचित किया जाता है कि 04 मार्च 2026 होली के अवसर पर हमारा कार्यालय बंद रहेगा। अतः 05 मार्च 2026 का अंक प्रकाशित नहीं किया जाएगा।, आगामी अंक 06 मार्च, 2026 शुक्रवार से यथावत अंक प्रकाशित होंगे। सभी को होली की हार्दिक शुभकामना।

-सम्पादक

गुजरात उच्च न्यायालय ने पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य कर दिया है, आरटीआई फुटेज को 30 दिनों तक सुरक्षित रखना होगा

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत।

गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्येक पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी लगाना अनिवार्य करने के आदेश के संबंध में, अब राज्य के सभी पुलिस स्टेशनों को सीसीटीवी लगाना होगा। इतना ही नहीं, गुजरात उच्च न्यायालय ने उन पुलिस स्टेशनों के खिलाफ कार्रवाई का भी आदेश दिया है जिन्होंने सीसीटीवी नहीं लगाया है और यदि लगाया भी है लेकिन बंद अवस्था में है।

शून्य त्रुटि एजेंसी

इसके साथ ही अदालत ने सरकार और गृह विभाग को निर्देश भी दिए थे। अब सूचना आयोग ने सीसीटीवी को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। पुलिस को मिली शिकायतों और अभ्यावेदनों के आधार पर सूचना आयोग ने फैसला सुनाया था कि आरटीआई के तहत सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। इस फैसले में कहा गया है कि अगर घटना के 30 दिनों के भीतर आरटीआई दाखिल की जाती है, तो सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखना होगा। अगर मांगी गई फुटेज नष्ट की जाती है, तो कार्रवाई की जाएगी।

सूचना आयोग ने सीसीटीवी फुटेज संबंधी परिपत्र को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए थे। इसके अलावा, सूचना आयोग ने

राज्य पुलिस प्रमुख सहित

सभी अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने के संबंध में एक और परिपत्र जारी करने का निर्देश दिया था । हाल ही में, शहर के कोटडा पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी को लेकर एक शिकायत दर्ज की गई थी।

यह मामला सूचना आयोग तक पहुंचा क्योंकि पुलिस ने आरटीआई के तहत सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध नहीं कराया था।

इसलिए, सूचना आयोग ने सीसीटीवी फुटेज से संबंधित सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया था

। सूचना आयोग ने अपने फैसले में कहा था कि

घटना के 30 दिन बाद तक सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखना आवश्यक है। अब देखना यह है कि इसे कब लागू किया जाएगा?

संपादकीय

आर्थिक उथल-पुथल

भले ही, दुनिया में चौधराहट बनाये रखने और साम्राज्यवादी मंसूबों को पूरा करने के लिए अमेरिका ने इस्राइल के साथ मिलकर ईरान पर युद्ध थोपा हो, मगर इस युद्ध के दूरगामी घातक परिणाम पूरी दुनिया को झेलने होंगे। इस संघर्ष ने पूरे पश्चिमी एशिया को गहरे संकट में डाल दिया है। तबाही के कगार पर खड़े ईरान ने जिस तरह अपने पड़ोसी देशों के व्यापारिक व औद्योगिक संस्थानों पर ताबड़-तोड़ हमले किए हैं, उससे मध्यपूर्व में बड़ा आर्थिक संकट पैदा हो गया है। लाखों लोगों के रोजगार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। खासकर लाखों भारतीय कामगारों के लिये बड़ा संकट पैदा हो गया है। ईरान की जवाबी कार्रवाई से पश्चिमी एशिया में बढ़ते संकट से, इस क्षेत्र में आर्थिक उथल-पुथल मची हुई है। दुनिया के प्रमुख वैश्विक जहाजरानी मार्गों पर मंडरा रहे खतरे के बीच ऊर्जा बाजार की स्थिति पर गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। होर्मुज जलडमरूमध्य के पास हुए हमलों के कारण कच्चे तेल और द्रवीकृत प्राकृतिक गैस यानी एलएनजी की ढुलाई पहले ही बाधित हो चुकी है। उल्लेखनीय है कि होर्मुज जलडमरूमध्य वैश्विक तेल आपूर्ति के लगभग पांचवें हिस्से के लिये एक रणनीतिक मार्ग है। लेकिन मौजूदा युद्ध से उपजे हालात में जहाज बीमा कंपनियों ने युद्ध-जोखिम कवरेज वापस ले लिया है। इसके चलते पेट्रोलियम पदार्थों व अन्य उत्पादों की माल ढुलाई लागत बढ़ रही है। युद्ध की विभीषिका के चलते तमाम जहाजों ने अपने मार्ग बदल लिए हैं। कुछ जहाज चलाने वाली कंपनियों ने अपने जहाजों के परिचालन पर रोक लगा दी है। इसका तात्कालिक परिणाम यह है कि कच्चे तेल की कीमतों में काफी उछाल देखा जा रहा है। जिसके चलते ब्रेंट क्रूड की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि देखी जा रही है। इसमें दो राय नहीं कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें आने वाले दिनों में विश्व स्तर पर मुद्रास्फीति के दबाव को बढ़ाएंगी। जाहिरा तौर पर विकासशील व गरीब देशों का आर्थिक संकट और गहरा हो जाएगा।

वहीं दूसरी ओर विकासशील देशों की सरकारों के सामने विकास कार्यक्रमों के लिये वित्तीय संसाधन जुटाना अब एक बड़ी चुनौती होगी। वहीं इन देशों में केंद्रीय बैंकों के लिये भी मुद्रास्फीति और विकास के बीच संतुलन बनाये रखना मुश्किल हो जाएगा। दरअसल, हाल के दिनों में पेट्रोलियम और उसके उत्पादों पर निर्भर परिवहन, रसायन और प्लास्टिक उद्योग तक को बढ़ती लागत का सामना करना पड़ रहा है। जाहिर है इससे इन उद्योगों के लाभ में कमी आ सकती है। साथ ही इन उद्योगों में निवेश धीमा हो सकता है। वहीं दूसरी ओर आपूर्ति में देरी से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं की समस्याएं और भी बढ़ सकती हैं। यह सर्वविदित है कि आज भी भारत अपनी घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिये कच्चे तेल का अस्सी से नब्बे प्रतिशत आयात करता है। इस कच्चे तेल का करीब चालीस फीसदी हिस्सा पश्चिमी एशिया से आता है। मौजूदा विषम परिस्थितियों के बीच होर्मुज जलमार्ग में व्यवधान तथा भू-राजनीतिक जोखिमों में वृद्धि से भारत के तेल आयात बिल के बढ़ने की आशंका बढ़ गई है। वहीं इसके साथ ही देश का राजकोषीय घाटा भी बढ़ सकता है। यहां तक कि कच्चे तेल के दाम में दस डॉलर प्रति बैरल की वृद्धि भी आयात लागत को काफी हद तक बढ़ा सकती है। मौजूद संकट के बीच, विशेष रूप से खाड़ी क्षेत्र को निर्यात के लिये बने व्यापार गलियारे आज जटिल परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर होर्मुज जलमार्ग और आगे के माल ढुलाई नेटवर्क के माध्यम से शिपिंग पर निर्भर इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य वस्तुओं के निर्यात में देरी से लागत के बढ़ने की आशंका है। साथ ही अवसरों के नुकसान होने का खतरा बढ़ रहा है। यूं तो भारत सरकार आत्मविश्वास से भरी नजर आती है, लेकिन यदि पश्चिम एशिया का संघर्ष लंबा चलता है, तो हालात आर्थिक चुनौतियों को काफी हद तक बढ़ा सकते हैं। इस संकट से निपटने के लिए त्वरित नीतिगत प्रतिक्रिया की जरूरत है। वक्त की मांग है कि लगातार विषम होती परिस्थितियों के बीच ऊर्जा स्रोतों का विविधीकरण किया जाये। वहीं दूसरी ओर अस्थिरता से बचाव के लिये तत्काल मजबूत आर्थिक सुरक्षा उपायों की आवश्यकता होगी।

बाहरी चमक-दमक में सिसकता अमेरिकी समाज

> अमेरिका ने चतुराई से अपनी कैसी छवि बनाई है कि हम उसे इस धरती का स्वर्ग मानने लगे हैं, जबकि यदि नर्क जैसी कोई जगह होती हो, तो यह देश उससे भी बड़ा है। दुनियाभर में दरोगाई करके अमेरिका ने जितने अत्याचार किए हैं और कर रहा है, उसकी मिसाल मिलना दुर्लभ है।

हाल ही में अमेरिका के उच्चतम न्यायालय ने ट्रंप के मनमाने तरीके से टैरिफ लगाने के फैसले को पलटा। बदले में वहां के न्यायाधीशों को लेकर ट्रंप ने गाली-गलौज की भाषा का इस्तेमाल किया, उससे यही पता चलता है कि उनकी आस्था लोकतांत्रिक मूल्यों में कतई नहीं है। बल्कि जिस तरह के बयान वे लगातार दे रहे हैं, वे भी बताते हैं कि उन्हें किसी की परवाह नहीं है। उनकी ऐसी बातें सुनकर अनेक ऐसी कहानियां याद आती हैं, जहां कोई राजा-महाराजा अपने को अमर समझता था और दुर्दिनों को प्राप्त होता था।

अमेरिका में इन दिनों उन लोगों की बाढ़ आई हुई है, जो सड़कों पर उतरे हुए हैं। वे भारतीयों को तरह-तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं। नफरती बयान दे रहे हैं। उनके पूजा स्थलों को निशाना बना रहे हैं। जिस तरह से वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाया और दुनिया के अधिकांश देशों ने चुप्पी साध ली, वह तुलसीदास जी की सैकड़ों वर्ष पहले लिखी बात को सच साबित करता है 'समरथ को नहिं दोष गुसाईं'। लेकिन कोई भी सामर्थ्यवान हमेशा समर्थ नहीं रहता। यह भी याद रखना चाहिए।

पूरी दुनिया के युवा जिन्हें जेनरेशन जी के नाम से पुकारा जाता है, वे अमेरिका को किसी ड्रीम कंट्री की तरह देखते रहे हैं। भारत में भी बच्चे की सफलता इस बात से तय मानी जाती है कि वह अमेरिका गया कि नहीं। लेकिन अब ये सपने टूट रहे हैं। वहां के विश्वविद्यालयों में भारतीय छात्रों का एनरोलमेंट लगातार गिर रहा है। अमेरिका बस श्वेत अमेरिकियों के लिए है, ये भावना वहां सिर उठा रही है। इसलिए बाहर के बच्चे वहां जाने से बच रहे हैं।

अमेरिका की आबादी मात्र चौंतीस-पैंतीस करोड़ है। लेकिन अपराधों का आंकड़ा बहुत बड़ा है। स्त्रियों के प्रति अपराध बड़ी संख्या में होते हैं। आबादी के मुकाबले दुगुने हथियार हैं। ये सरे बाजार मिलते हैं। बच्चे ड्रग्स की चपेट में हैं। ड्रग्स खुले बाजार में मिलती हैं और बच्चे भी इन्हें खरीद सकते हैं। उन्हें कोई रोक भी नहीं सकता। यदि कोई रोके, तो इसे बच्चों के अधिकारों के खिलाफ माना जाता है।

हाल ही में पेंग्विन में छपे तीन उपन्यासों को पढ़ा था। ये हैं—ब्वॉयफ्रेंड, झूठ मत बोलो और हादसा। इसकी लेखिका फ्रीडा मैकफेडन हैं। फ्रीडा पेशे से दिमाग की चोटों की एक्सपर्ट डाक्टर हैं। लेकिन क्राइम थ्रिलर और कामेडी भी लिखती हैं। अब तक उनकी रचनाओं के विश्व की चालीस भाषाओं में अनुवाद हो चुके हैं।

इन उपन्यासों को पढ़ते हुए लगा कि वे अमेरिका के जीवन को कितनी नजदीक से जानती हैं। तीनों के तीनों उपन्यास ऐसे हैं, जिनसे पता लगता है कि वहां के समाज में आप किसी पर विश्वास नहीं कर सकते। भाई-बहन पर नहीं, बहन भाई पर नहीं। पति-पत्नी पर नहीं, पत्नी पति पर नहीं। मरीज डाक्टर पर नहीं, और डाक्टर मरीज पर नहीं। इनमें से अधिकतर अपने आसपास वालों की हत्या कर देते हैं। गाड़ी के ब्रेक खराब कर देते हैं। इनकी लाशों को घरों के तहखानों में डाल दिया जाता है। वे वहां सड़ जाती हैं। या किसी जंगल में जाकर गाड़ दिया जाता है। बच्चे की चाह में किसी महिला को मदद के बहाने अपने घर के तहखाने में रख दिया जाता है। एक लड़की का एक्सीडेंट होता है। गाड़ी बर्फ में फंस जाती है। उसे एक आदमी अपने घर लाता है। लड़की गर्भवती है। घर की निःसंतान महिला को लगता है कि यदि यह लड़की बच्चे को यहां जन्म दे दे, तो वह बच्चे को हड़प लेगी और इस लड़की को ठिकाने लगा देगी। मगर उसका पति एक दिन उसकी अनुपस्थिति में उस लड़की को अस्पताल में छोड़ आता है। वहां लड़की का सगा भाई उसे मारने की कोशिश करता है। पहले भी वह लड़की के कार के ब्रेक खराब कर चुका है, क्योंकि वह उस आदमी से मिला हुआ है, जो लड़की का दुष्कर्मी है। ये पढ़ते-पढ़ते आप थरथराने लगते हैं कि ये कैसा समाज है। जहां हर कोई बस दूसरे की जान लेने की कोशिश में है। रिश्तों की कोई मर्यादा भी नहीं। अपने देश में होने वाली ऐसी बहुत-सी घटनाएं याद आने लगती हैं। अमेरिका तो कहता है कि वह पूरे विश्व का ठेकेदार है, लेकिन अपने यहां के अपराध नहीं रोके जाते। इन उपन्यासों में पुलिस बुलाते ही आ भी जाती है, लेकिन अधिकांश बार वह न तो अपराधी को पकड़ पाती है, न ही लाश को ढूंढ़ पाती है। और सबसे बड़ी बात ये कि अपराधी खूब मजे से, सारी सुविधाओं का लाभ उठाते हुए जीवन जीते हैं। पार्टी करते हैं। एक घर में रहते हुए भी वे एक-दूसरे को धोखा देते रहते हैं। उन्हें कोई पछतावा भी नहीं होता। यहां घर बहुत बड़े-बड़े हैं। दूर-दूर तक कोई अड़ोसी-पड़ोसी भी नजर नहीं आता। ऐसे में लगता है कि कोई अपराध हो तो उसकी सूचना भी कैसे दी जाए। इसीलिए लोग अपने घरों में अलार्म सिस्टम लगवाते हैं। न्यूयार्क जिसे अमेरिका की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, वहां एक नहीं कई-कई ताले लगाए जाते हैं, लेकिन ताले या अलार्म सिस्टम अपराधों को नहीं रोक पाते। फिर वे अपराध रुकें भी कैसे, जिन्हें अपने ही अंजाम दे रहे हैं।

इन्हें पढ़ते हुए सोचती रही कि बाहरी देशों में अमेरिका ने चतुराई से अपनी कैसी छवि बनाई है कि हम उसे इस धरती का स्वर्ग मानने लगे हैं, जबकि यदि नर्क जैसी कोई जगह होती हो, तो यह देश उससे भी बड़ा है। दुनियाभर में दरोगाई करके अमेरिका ने जितने अत्याचार किए हैं और कर रहा है, उसकी मिसाल मिलना दुर्लभ है।

उपन्यास या कहानियों के बारे में कहा जाता है कि वे काल्पनिक होती हैं, लेकिन वे पूरी तरह से काल्पनिक भी नहीं होतीं। वे अपने देशकाल को बताती हैं और इस तरह इतिहास का हिस्सा भी बनती हैं। वे अपने समकालीन समाज को दिखाने वाले बेजोड़ दस्तावेज भी होते हैं।

यों तो फिल्मों के बारे में भी यह कह सकते हैं। फिल्में भी अपने समय की साक्षी होती हैं। अमेरिकी जीवन में कितनी मारामारी है, इसे हॉलीवुड की फिल्में खूब दिखाती हैं। लेकिन फिल्म के मुकाबले किताब का असर ज्यादा होता है। किताबों से जो दृश्य लगातार आपके मन में बनते हैं, वे गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। इसीलिए दृश्य माध्यम चाहे भुला दिए जाएं, किताबों का असर बहुत दिनों तक रहता है। इन दिनों सोशल मीडिया के जमाने में बहुत सी स्त्रियां-पुरुष, अपने अनुभव लिखते हैं, जिन्हें दुनियाभर में कोई भी पढ़ सकता है।

एक अमेरिकी महिला ने कुछ दिन पहले अपनी आपबीती लिखी थी कि किस तरह से जिस मकान को उसने अपनी मेहनत की कमाई से बनाया था, वहां अपनी पसंद के गुलाब और अन्य पौधे लगाए थे। उसकी साथ न रहने वाली बहू, रोज उससे कहने लगी कि आप इस घर को छोड़कर वृद्धाश्रम चली जाएं। अब इस घर में आप जैसी वृद्धा का नहीं, हमारे रहने का अधिकार है। और तो और बहू ने अपने दोस्तों के लिए सास के वृद्धाश्रम जाने के उपलक्ष्य में एक विदाई पार्टी भी आयोजित की। तब महिला को अपने बहू-बेटे को घर से निकलवाने के लिए पुलिस की मदद लेनी पड़ी।

प्रेरणा

अंतरात्मा की पुकार और नैतिक विद्रोह की शक्ति

उन्नीसवीं शताब्दी के अमेरिका में जब समाज दासप्रथा, युद्ध और राजनीतिक विस्तारवाद की जटिलताओं से गुजर रहा था, तब एक शांत स्वभाव का चिंतक अपने भीतर उठती नैतिक आवाज़ को सुन रहा था। उसका नाम था Henry David Thoreau। वह कोई सैनिक नहीं था, न ही कोई बड़ा राजनेता, पर उसके भीतर सत्य के प्रति ऐसी निष्ठा थी जिसने उसे इतिहास में अमर कर दिया। उसने यह सिद्ध किया कि कभी-कभी सबसे बड़ा संघर्ष तलवार से नहीं, बल्कि अंतःकरण से लड़ा जाता है।

थोरौ का मानना था कि नागरिक केवल कानूनों का पालन करने के लिए नहीं जन्मा है; वह न्याय और अन्याय का विवेकपूर्ण निर्णय करने की क्षमता भी रखता है। जब सरकार ने ऐसा कर लगाया जिसका उपयोग उन नीतियों के समर्थन में हो रहा था जिन्हें वह अन्यायपूर्ण मानते थे, तो उन्होंने कर देने से इंकार कर दिया। यह निर्णय व्यक्तिगत सुविधा के विरुद्ध था, क्योंकि वे जानते थे कि इसका परिणाम कारावास हो सकता है। फिर भी उन्होंने अपने सिद्धांतों को प्राथमिकता दी।

उनकी गिरफ्तारी ने समाज को चौंका दिया। एक विद्वान, लेखक और प्रकृतिप्रेमी को जेल में देखना लोगों के लिए असामान्य था। रात को उनका एक परिचित उनसे मिलने आया और आश्चर्य से पूछा कि इतनी छोटी-सी बात के लिए स्वयं को संकट में डालना क्या उचित है। उसने सुझाव दिया कि कर दे देना अधिक व्यावहारिक होता। तब थोरौ ने शांत स्वर में कहा कि यदि वे अन्याय को स्वीकार कर लेते, तो बाहर रहकर भी भीतर से कैदी होते। उनके लिए जेल की दीवारें कम भयावह थीं, अपने विवेक के विरुद्ध जाना अधिक भयावह था।

यह प्रसंग हमें यह समझाता है कि सच्ची स्वतंत्रता केवल बाहरी परिस्थिति नहीं, बल्कि मानसिक और नैतिक अवस्था है। यदि व्यक्ति अपने सिद्धांतों से समझौता कर ले, तो वह चाहे कितनी भी सुविधाओं में रहे, भीतर से बंधा रहता है। थोरौ ने यह दिखाया कि नैतिक स्वतंत्रता बाहरी स्वतंत्रता से कहीं अधिक मूल्यवान है। उनका यह विचार आगे चलकर "सिविल नाफरमानी" के रूप में प्रसिद्ध हुआ, जिसमें अन्यायपूर्ण कानूनों के विरुद्ध शांतिपूर्ण असहयोग को उचित ठहराया गया।

उनकी यह सोच केवल अमेरिका तक सीमित नहीं रही। भारत में जब Mahatma Gandhi ने ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण कानूनों के विरुद्ध सत्याग्रह प्रारंभ किया, तो उन्होंने भी शांतिपूर्ण असहयोग को ही चुना। गांधीजी ने स्पष्ट कहा था कि अन्याय के साथ सहयोग करना स्वयं अन्याय में भागीदार होना है। इसी प्रकार अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन के दौरान Martin Luther King Jr. ने भी थोरौ के सिद्धांतों को अपनाया। इस प्रकार एक व्यक्ति का नैतिक निर्णय विश्वभर में परिवर्तन की प्रेरणा बन गया।

सत्य के मार्ग पर चलना आसान नहीं होता। जब व्यक्ति भीड़ से अलग खड़ा होता है, तो उसे आलोचना, उपहास और कभी-कभी दंड का सामना करना पड़ता है। समाज अक्सर सुविधा और परंपरा के आधार पर चलता है, जबकि सत्य कई बार असुविधाजनक होता है। थोरौ ने यह जोखिम स्वीकार किया, क्योंकि वे जानते थे कि सिद्धांतों से समझौता करना आत्मसम्मान खो देने के समान है। उनके लिए सम्मान बाहरी प्रतिष्ठा से नहीं, बल्कि भीतर की शांति से जुड़ा था।

जब वे जेल से रिहा हुए, तो लोगों ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें डर नहीं लगा। उनका उत्तर अत्यंत सारगर्भित था—डर जेल में नहीं था, डर अन्याय के साथ खड़े होने में था। यह वाक्य हमें आत्मचिंतन के लिए प्रेरित करता है। हम प्रायः बाहरी परिस्थितियों से डरते हैं—नौकरी खोने का भय, समाज के विरोध का भय, असफलता का भय। परंतु सबसे बड़ा भय अपने मूल्यों को खो देने का होना चाहिए। यदि हम अपने सिद्धांतों को छोड़ दें, तो बाहरी सफलता भी भीतर की शांति नहीं दे सकती।

आज के समय में भी यह संदेश उतना ही महत्वपूर्ण है। आधुनिक समाज में प्रतिस्पर्धा और दबाव इतने अधिक हैं कि व्यक्ति कई बार सुविधा के लिए समझौता कर लेता है। कभी वह गलत प्रथाओं को अनदेखा करता है, कभी चुप रहकर अन्याय को सहन करता है। परंतु यदि प्रत्येक व्यक्ति यह ठान ले कि वह अन्याय का समर्थन नहीं करेगा, तो परिवर्तन अवश्य संभव है। परिवर्तन की शुरुआत हमेशा एक व्यक्ति से होती है, जो अपने अंतःकरण की आवाज़ सुनने का साहस करता है।

थोरौ का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि विरोध का अर्थ हिंसा नहीं है। उन्होंने शांतिपूर्ण असहयोग को चुना। उन्होंने किसी के प्रति घृणा नहीं दिखाई, बल्कि व्यवस्था की नैतिकता पर प्रश्न उठाया। यही नैतिक विद्रोह की शक्ति है—यह क्रोध से नहीं, स्पष्टता और आत्मविश्वास से उत्पन्न होता है। जब विरोध संयमित और सिद्धांतपूर्ण हो, तो वह अधिक प्रभावशाली बन जाता है।

उनकी यह शिक्षा केवल राजनीतिक संदर्भ तक सीमित नहीं है। व्यक्तिगत जीवन में भी हम अनेक नैतिक निर्णयों का सामना करते हैं। चाहे कार्यस्थल हो, परिवार हो या समाज—हर जगह ऐसे क्षण आते हैं जब हमें सुविधा और सत्य में से किसी एक को चुनना पड़ता है। यदि हम सत्य का चयन करते हैं, तो संभव है कि हमें तत्काल लाभ न मिले, परंतु दीर्घकाल में वही निर्णय हमें आत्मसम्मान और संतोष प्रदान करता है।

अंततः थोरौ की कथा यह बताती है कि एक जागृत अंतःकरण समूचे समाज को दिशा दे सकता है। जब एक व्यक्ति सत्य के लिए खड़ा होता है, तो वह दूसरों के भीतर भी साहस जगाता है। उसकी दृढ़ता एक चिंगारी की तरह होती है, जो धीरे-धीरे प्रकाश फैलाती है। इतिहास के अनेक परिवर्तन ऐसे ही छोटे-छोटे नैतिक निर्णयों से प्रारंभ हुए हैं। इसलिए यदि हमें सच्ची स्वतंत्रता चाहिए, तो हमें अपने भीतर की आवाज़ को महत्व देना होगा। बाहरी बंधन उतने शक्तिशाली नहीं होते जितना भीतर का भय। जब हम उस भय को पराजित कर लेते हैं, तब हम वास्तव में स्वतंत्र हो जाते हैं। थोरौ का जीवन यही संदेश देता है कि सिद्धांतों पर अडिग रहना ही सच्ची मुक्ति है। जो व्यक्ति सत्य के लिए अकेला खड़ा होने का साहस रखता है, वही समाज के लिए मार्गदर्शक बनता है।

आखिर अमेरिकी वर्चस्व की कीमत कबतक चुकाएगी शेष दुनिया?

महाकवि तुलसीदास ने 'रामचरितमानस' में लिखा है कि "समरथ को नहीं दोष गोसाईं।" यानी कि ताकतवर लोगों को कोई भी दैव दोष तक नहीं लगता है! यदि समकालीन लोकतांत्रिक कसौटियों और प्रवृत्तियों में इसे देखें तो देश-दुनिया के सभी वैधानिक नियमन शक्तिशाली देशों और लोगों के ही पक्ष में कार्य करते प्रतीत होते हैं। वाकई उनके किसी भी लोकविरोधी या जनविरोधी कार्य में प्रायः कोई न्यायिक बाधाएं तक नजर नहीं आतीं और न ही उनमें कोई दोष या खामियां तलाशी जाती हैं। आलम यह है कि किसी भी संसद, सर्वोत्तम न्यायालय या फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तक में ऐसे मामले पर ज्यादा सवाल जवाब नहीं किये जाते और अंततः मामले रफादफा कर, करवा दिए जाते हैं। कबीलाई भाषा में कहें तो जिसकी लाठी, उसकी भैंस वाली कहावत न केवल ग्रामीण जगत की मानसिकता बल्कि आधुनिक नृशंस विश्व के मानस पटल तक पर हावी महसूस होता है। बहरहाल इससे बचने का कोई रास्ता भी नजर नहीं आता। सच कहूं तो "वीर भोग्या वसुंधरा" वाली कहावत प्रायः हर जगह चरितार्थ होती आई है।

देखा जाए तो समकालीन दुनिया भी अमेरिकी वर्चस्व की यही स्थिति है, जिसकी भारी कीमत शेष चुकाती आई है और आगे भी चुकाती रहेगी इन कीमतों में सैन्य हस्तक्षेपों से उत्पन्न युद्ध, तरह तरह से आर्थिक शोषण और डॉलर-प्रधान मौद्रिक व्यवस्था शामिल हैं। वैसे तो अमेरिका का सबसे बड़ा रक्षा बजट और वैश्विक सैन्य अड्डे नेटवर्क अन्य देशों पर हमेशा दबाव बनाए रखते हैं, जबकि डॉलर डिप्लोमेसी और डॉलर की आरक्षित मुद्रा स्थिति विकासशील देशों को आर्थिक निर्भरता में बांधती है।

यही वजह है कि अमेरिकी वर्चस्व की वैश्विक लागत आएदिन बढ़ती जा रही है और उसके नानाविध हथकंडे से दुनियावी देशों को असहमति की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। पहले की बात छोड़ भी दी जाए तो हाल ही में बेनेजुएला की सरकार के बाद ईरान की सरकार का जो हश्र अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने कर दिखाया है, वह बिल्कुल ताजा और नया उदाहरण बनकर उभरा है, जहां ईरान को समर्थन देने वाले अंतर्राष्ट्रीय देशों की बेचारगी भी स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो जाती है। जी हां, रूस-चीन-उत्तरकोरिया गठजोड़ की, जिन्होंने ईरानी तानाशाह खामेनेई को मनबढ़ बनवाकर मरवा दिया और हाथ पर हाथ धरे रहकर तमाशा देखते रहे या विरोध की औपचारिकता भर निभाते रहे।

यदि अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर आपने गौर किया होगा तो स्पष्ट महसूस हुआ होगा कि इराक-अफगानिस्तान जैसे लंबे संघर्षों से अमेरिकी सैन्य अतिभारण बढ़ा, जिससे वैश्विक अस्थिरता और आर्थिक बोझ बढ़ा। वहीं, कोई भी देश डॉलर प्रभुत्व से अमेरिकी ऋण आसानी से ले सकता है, लेकिन अन्य देशों को महंगाई और व्यापार असंतुलन का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा, पेट्रोडॉलर सिस्टम तेल व्यापार को डॉलर में बांधता है, जो चीन जैसे आयातकों के लिए नुकसानदेह है।

हालांकि, अमेरिकी वर्चस्व में यदाकदा क्षय के संकेत भी मिलते आए हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका का जो रक्तरंजित चेहरा खुलकर सामने आया है वह अमेरिका को चुनौती देने की सोच रखने वाले देशों को किसी खुली नसीहत की तरह है। पहले टैरिफ युद्ध और अब खुली जंग ने यह साफ कर दिया है कि "मेक अमेरिका ग्रेट अगेन" के मार्ग पुनः प्रशस्त हो चुके हैं। इसमें डीप स्टेट की भूमिका से भी इंकार नहीं किया जा सकता है। वहीं अपने आक्रामक रुख और शातिर कूटनीति से जिस तरह से उन्होंने ब्रिक्स देशों की बखिया उधेड़नी शुरू की है, ऐसा उदाहरण अतीत में 1944 के बाद कभी नहीं मिला है।

यूं तो 2010 की भविष्यवाणी के अनुसार, अमेरिकी प्रभुत्व 2025 तक कमजोर हो सकता था, जो आंतरिक विभाजन और प्रतिद्वंद्वियों के उदय से सत्य सिद्ध हो रही है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आक्रामक प्रशासन ने अब स्थिति को अपने पक्ष में बदलने में कामयाबी हासिल कर ली है। इसके लिए अमेरिकियों को ट्रंप को बधाई देनी चाहिए। भले ही 2026 में डॉलर 10% गिरा, ब्याज दर अंतर कम होने से दबाव बढ़ा, लेकिन अब वह मुनाफे में रहेंगे, क्योंकि दुनिया को पुनः अस्थिर करने में उन्होंने कामयाबी हासिल कर ली है। वहीं BRICS (40% वैश्विक GDP) अब SWIFT विकल्प और राष्ट्रीय मुद्राओं पर जोर दे रहा है। लेकिन अमेरिकी आक्रामकता जल्द ही सबकुछ अपने हित के अनुकूल कर लेगी।

इस बात में कोई दो राय नहीं कि बहुध्रुवीय विश्व उभर रहा है, जहां चीन, रूस, भारत और यूरोपीय संघ जैसे देश शक्ति बांट रहे हैं। इसके बावजूद, इनके आंतरिक और नीतिगत अंतर्विरोधों से अब यह साफ हो चुका है कि अमेरिकी प्रभुत्व तत्काल समाप्त नहीं होगा, बल्कि ट्रंप प्रशासन की नीतियां (जैसे UNO, WHO से अलग राह) इसे और तेज कर सकती हैं। लिहाजा शेष दुनिया अमेरिकी हौसलों और दूरदर्शिता भरे लोकतांत्रिक षड्यंत्रों की कीमत चुकाना जारी रखेगी जब तक BRICS जैसी पहलें मजबूत न हों।

भले ही चीन अमेरिकी वर्चस्व को आर्थिक, सैन्य, कूटनीतिक और तकनीकी मोर्चों पर बहुआयामी चुनौती दे रहा है। जिससे यह चुनौती बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की ओर इशारा करती है, जहां चीन वैकल्पिक मॉडल प्रस्तुत कर रहा है। जहां आर्थिक मोर्चा पर चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के जरिए 140+ देशों में निवेश बढ़ाया, जो अमेरिकी प्रभाव वाले क्षेत्रों में कर्ज जाल और बंदरगाह नियंत्रण बनाता है। वहीं डॉलर प्रभुत्व को चुनौती देते हुए, चीन BRICS के माध्यम से डी-डॉलरीकरण को बढ़ावा दे रहा है, जिसमें राष्ट्रीय मुद्राओं का उपयोग और नई भुगतान प्रणाली शामिल है। यही वजह है कि 2026 तक चीन की GDP अमेरिका के करीब पहुंच चुकी है, EV और AI जैसे क्षेत्रों में चीन, अमेरिका से आगे निकल चुका है।

अभियान

प्रेम, कीर्तन और करुणा की धारा: श्री चैतन्य महाप्रभु का दिव्य जीवन-वृत्त

भक्ति आंदोलन की उज्ज्वल परंपरा में यदि किसी संत ने प्रेम को साधना का सर्वोच्च शिखर बनाया, तो वे थे Chaitanya Mahaprabhu। फाल्गुन पूर्णिमा के पावन दिवस पर सन् 1486 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के नादिया जनपद स्थित मायापुर धाम में उनका अवतरण हुआ। पिता जगन्नाथ मिश्र और माता शची देवी के घर जन्मे इस बालक का नाम प्रारंभ में 'निमाई' रखा गया, क्योंकि उनका जन्म नीम के वृक्ष के नीचे हुआ था। उनका गौर वर्ण इतना मनोहर था कि लोग उन्हें गौरांग, गौरहरि और गौरसुंदर कहकर पुकारने लगे। किंतु यह बालक आगे चलकर केवल एक परिवार या क्षेत्र का नहीं, बल्कि समूची मानवता के हृदय में प्रेम का दीप जलाने वाला संत सिद्ध हुआ। बाल्यावस्था से ही निमाई असाधारण प्रतिभा के धनी थे। वे तर्क, व्याकरण और शास्त्रार्थ में विलक्षण कौशल रखते थे। नवद्वीप उस समय विद्या का प्रमुख केंद्र था और युवा निमाई वहां के प्रख्यात पंडितों में गिने जाते थे। किंतु ज्ञान की यह प्रखरता अभी भक्ति की मधुरता से पूरी तरह संयुक्त नहीं हुई थी। उनका जीवन तब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंचा जब वे गया धाम में अपने पिता का श्राद्ध करने गए। वहीं उनकी भेंट महान वैष्णव संत Ishvara Puri से हुई। ईश्वर पुरी जी ने उनके कान में श्रीकृष्ण नाम का मंत्र दिया। कहा जाता है कि उस दीक्षा के बाद निमाई का अंतर्मन पूर्णतः परिवर्तित हो गया। विद्वत्ता का गर्व गलकर प्रेम की धारा में बह गया, और वे कृष्ण-प्रेम में निमग्न हो उठे।

उनका वैवाहिक जीवन भी जीवन की लीला का एक अध्याय रहा। किशोरावस्था में उनका विवाह लक्ष्मीप्रिया से हुआ, किंतु अल्प समय में ही उनका देहावसान हो गया। बाद में उनका विवाह विष्णुप्रिया से हुआ, जो अत्यंत पतिव्रता और धर्मनिष्ठ थीं। किंतु निमाई का अंतर्मन अब सांसारिक बंधनों से परे हो चुका था। महज चौबीस वर्ष की आयु में उन्होंने गृहत्याग कर संन्यास ग्रहण करने का निश्चय किया। संन्यास दीक्षा उन्हें Keshava Bharati से प्राप्त हुई, और तभी से वे 'चैतन्य' नाम से विख्यात हुए। यह संन्यास केवल वस्त्र परिवर्तन नहीं था, बल्कि संपूर्ण जीवन को कृष्ण-प्रेम के प्रचार हेतु समर्पित कर देने का संकल्प था।

गौड़ीय वैष्णव परंपरा में उन्हें श्रीकृष्ण का अवतार माना गया है—ऐसा अवतार जो राधा भाव से युक्त होकर स्वयं अपने प्रेम का आस्वादन करने पृथ्वी पर अवतीर्ण हुआ। इस भाव को बाद में अनेक आचार्यों ने अपने ग्रंथों और कीर्तनों में प्रतिपादित किया। उनका कीर्तन केवल संगीत नहीं था; वह प्रेम की ज्वाला थी, जो श्रोताओं के हृदय को द्रवित कर देती थी। वे हरिनाम संकीर्तन को साधना का सर्वश्रेष्ठ साधन बताते थे। उनका संदेश स्पष्ट था—कलियुग में केवल हरिनाम ही मोक्ष का पथ है। संन्यास के बाद उन्होंने भा तवर्ष की पदयात्रा की। नवद्वीप से पुरी, दक्षिण भारत से वृन्दावन तक वे निरंतर भ्रमण करते रहे। पुरी में उनका दीर्घ निवास रहा, जहां जगन्नाथ मंदिर की छाया में वे प्रेम-विह्वल होकर कीर्तन करते थे। उनके कीर्तन में ऐसा आकर्षण था कि साधारण जन से लेकर विद्वान पंडित तक सब उसमें बह जाते थे। उनके समकालीन दार्शनिक Sarvabhauma Bhattacharya और Prakasananda Saraswati भी प्रारंभ में उनके प्रति संशय रखते थे, किंतु अंततः उनके प्रेम और भक्ति के प्रभाव से प्रभावित होकर कृष्ण-भक्ति में प्रवृत्त हुए। यह परिवर्तन केवल तर्क से नहीं, बल्कि हृदय के स्पर्श से हुआ।

चैतन्य महाप्रभु का जीवन अद्भुत लीलाओं से परिपूर्ण था। कभी वे कीर्तन करते-करते भावसमाधि में चले जाते, कभी श्रीकृष्ण के विरह में अश्रुधारा बहाते। उनके लिए कृष्ण केवल पूजनीय देवता नहीं थे, बल्कि अंतरंग प्रियतम थे। वे कहते थे कि भक्ति का सर्वोच्च रूप वह है जिसमें भक्त स्वयं को पूर्णतः भूलकर केवल भगवान के प्रेम में डूब जाए। उनका यह भाव 'अचिन्त्य भेदाभेद' दर्शन के रूप में प्रतिपादित हुआ, जिसमें जीव और ब्रह्म के संबंध को अद्वितीय ढंग से समझाया गया—न तो पूर्णतः भिन्न, न पूर्णतः अभिन्न, बल्कि दोनों का अद्भुत समन्वय।

वृन्दावन की पुनर्स्थापना और वहां की लीलास्थलियों के पुनरुद्धार में भी उनका महान योगदान रहा। उन्होंने अपने छह प्रमुख शिष्यों—Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Jiva Goswami, Raghunatha Dasa Goswami, Raghunatha Bhatta Goswami और Gopala Bhatta Goswami—को वृन्दावन भेजा। इन षड्गोस्वामियों ने वहां प्राचीन लीलास्थलों की खोज की, मंदिरों की स्थापना की और वैष्णव साहित्य की रचना की। उनके प्रयासों से वृन्दावन पुनः भक्ति का केंद्र बना और वहां स्थापित देवालय आज भी श्रद्धालुओं को दिव्य शांति प्रदान करते हैं। चैतन्य महाप्रभु का संदेश केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं था। वे सामाजिक समरसता के भी पक्षधर थे। उनके कीर्तन में जाति, वर्ग और लिंग का कोई भेद नहीं था। वे कहते थे कि हर जीव में भगवान का अंश है, इसलिए सभी सम्मान के अधिकारी हैं। उस युग में जब समाज कठोर रूढ़ियों से बंधा था, उनका यह दृष्टिकोण अत्यंत क्रांतिकारी था। उन्होंने प्रेम को ही सर्वोच्च साधना और सर्वोच्च साध्य घोषित किया।

उनके जीवन का अंतिम काल पुरी में व्यतीत हुआ, जहां वे गहन आध्यात्मिक अनुभवों में निमग्न रहते थे। कहा जाता है कि वे श्रीकृष्ण के विरह में इतने द्रवित हो जाते कि कभी-कभी चेतना ही खो बैठते। उनके शरीर पर प्रेम के अद्भुत चिह्न प्रकट होते थे। यह सब उनके भीतर की उस दिव्य अनुभूति का प्रमाण था, जिसे शब्दों में बांधना कठिन है।

आज भी उनके द्वारा प्रारंभ की गई संकीर्तन परंपरा विश्वभर में जीवंत है। उनके अनुयायियों ने कृष्ण-नाम को गांव-गांव, नगर-नगर पहुंचाया। भक्ति को उन्होंने केवल व्यक्तिगत साधना नहीं, बल्कि सामूहिक उत्सव बना दिया। जब लोग एक साथ हरिनाम का कीर्तन करते हैं, तो वहां केवल संगीत नहीं, बल्कि सामूहिक चेतना का उदय होता है। यही उनकी साधना की विशिष्टता थी।

चैतन्य महाप्रभु का जीवन हमें यह सिखाता है कि प्रेम ही आध्यात्मिकता का सार है। ज्ञान और कर्म अपने स्थान पर महत्वपूर्ण हैं, किंतु यदि उनमें प्रेम का तत्व न हो, तो वे शुष्क रह जाते हैं। उन्होंने यह दिखाया कि भगवान तक पहुंचने का मार्ग कठिन तपस्या से नहीं, बल्कि निष्कपट प्रेम से भी संभव है। उनका जीवन एक ऐसी ज्योति है, जो यह स्मरण कराती है कि जब हृदय में भक्ति का उदय होता है, तब जीवन की समस्त पीड़ाएं तुच्छ प्रतीत होती हैं।

इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु केवल एक संत नहीं, बल्कि प्रेम के जीवंत अवतार थे। उनका कीर्तन आज भी युगों को जोड़ता है, उनका संदेश आज भी हृदयों को स्पर्श करता है, और उनकी करुणा आज भी मानवता को आलोकित करती है। प्रेम, समर्पण और हरिनाम की जिस धारा को उन्होंने प्रवाहित किया, वह आज भी अनवरत बह रही है और अनगिनत आत्माओं को प्रभु-प्रेम का अमृत पान करा रही है।

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

पांचवीं पास दीपक पटेल डेयरी क्षेत्र में 'मिरेकल बॉय' के रूप में उभरे : कृत्रिम गर्भाधान में 80 फीसदी गर्भधारण की सफलता दर के साथ देश में अव्वल

- दीपक पटेल की 80 फीसदी गर्भधारण की सफलता दर के चलते पशुपालकों को अधिक दुधारू पशु मिले और पशुओं की दुग्ध उत्पादन क्षमता भी बढ़ी
- देश में एक संकर गाय प्रतिदिन औसतन 7.4 लीटर दूध देती है
- गुजरात में एक संकर गाय प्रतिदिन औसतन 8.05 लीटर दूध देती है
- सूरत जिले की महुवा तहसील में एक संकर गाय प्रतिदिन 11.3 लीटर दूध देती है
- दीपक पटेल की कुशलता और समर्पण से हजारों पशुपालकों की आय बढ़ी

गांधीनगर : गुजरात के सूरत जिले की महुवा तहसील के वहेवल नामक एक छोटे से गांव में रहने वाले 5वीं पास 63 वर्षीय दीपक पटेल कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन के तौर पर अपनी असाधारण कुशलता के कारण देशभर में डेयरी उद्योग क्षेत्र में 'मिरेकल बॉय' के रूप में उभरकर सामने आए हैं।

दीपक पटेल ने पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान (आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन-एआई) के जरिए 80 फीसदी गर्भधारण की सफलता दर हासिल कर एक नया कीर्तिमान बनाते हुए भारत में इस क्षेत्र में प्रथम स्थान अर्जित किया है।

उनकी इस विशिष्ट उपलब्धि के चलते भारत के डेयरी उद्योग क्षेत्र से जुड़े लोग उन्हें 'मिरेकल बॉय' कहते हैं।

दीपक पटेल 1999 से सूरत जिला सहकारी दूध उत्पादक संघ लिमिटेड (सुमुल डेयरी) से जुड़े हुए हैं और कृत्रिम गर्भाधान के काम में लगे हुए हैं। उन्होंने पिछले दो दशकों से कृत्रिम गर्भाधान में 80 फीसदी गर्भधारण की सफलता दर को बनाए रखा है, जिसे एक असाधारण उपलब्धि कहा जा सकता है।

दीपक पटेल देश भर में अव्वल

विशेषज्ञों के अनुसार, भारत में कृत्रिम गर्भाधान की औसत सफलता दर 35 से 40 फीसदी है। वहीं, दीपकभाई की सफलता दर लगभग 80 फीसदी है। कृत्रिम गर्भाधान क्षेत्र में 80 फीसदी सफलता की यह दर राष्ट्रीय औसत के मुकाबले दोगुनी है।

दीपक पटेल की इस असाधारण कुशलता के कारण सूरत जिले के कई इलाकों में, विशेषकर महुवा तहसील में पशुओं की प्रजनन क्षमता, दुग्ध उत्पादन और किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

अब तक 80 हजार से अधिक कृत्रिम गर्भाधान की प्रक्रिया संपन्न की

सुमुल डेयरी के वेटरनरी विभाग के प्रमुख डॉ. अजीतसिंह जादव ने बताया कि सुमुल डेयरी द्वारा अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत सूरत और तापी जिले में प्रतिवर्ष लगभग पांच लाख कृत्रिम गर्भाधान किए जाते हैं। सुमुल डेयरी की कृत्रिम गर्भाधान की सफलता दर लगभग 53 फीसदी है।

दीपकभाई की विशेष दक्षता के कारण उनकी सफलता की दर लगभग 80 फीसदी है और उनकी इस सफलता का लाभ उनके क्षेत्र (महुवा) में पशुपालकों को मिलता है। यही कारण है कि इस क्षेत्र में न केवल दुधारू पशुओं की संख्या बढ़ रही है, बल्कि पशुओं की दुग्ध उत्पादकता भी अधिक है।

दीपक पटेल की सफलता का राज

दीपक पटेल की सफलता के राज को एक केस स्टडी के जरिए समझा जा सकता है। कुछ दिनों पहले एक पशुपालक ने उन्हें फोन किया और बताया कि उनकी गाय को कृत्रिम गर्भाधान की जरूरत है। दीपक पटेल पशुपालक के घर पहुंचे। गाय का निरीक्षण किया और पशुपालक को कुछ घंटे इंतजार करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि वह शाम को वापस आएंगे फिर कृत्रिम गर्भाधान की प्रक्रिया संपन्न करेंगे। वजह यह थी कि गाय अभी पूरी तरह से ताव (हीट) में नहीं आई थी, इसलिए यह समय कृत्रिम गर्भाधान के लिए उपयुक्त नहीं था। कृत्रिम गर्भाधान के लिए सटीक समय की पहचान करना ही उनकी असाधारण सफलता का मुख्य राज है।

सुमुल डेयरी के पूर्व प्रबंध निदेशक डॉ. पी.आर. पांडे ने कहा, "सुमुल डेयरी ने दीपकभाई की प्रतिभा को बहुत पहले ही पहचान लिया था। वे देश में सर्वाधिक 80 फीसदी की सफलता दर के साथ कृत्रिम गर्भाधान करने वाले तकनीशियन हैं। यह एक असाधारण सफलता है और उनकी इस कुशलता के कारण हजारों पशुपालकों की आय बढ़ी है और पशु नस्ल सुधार का काम तेज हुआ है।"

सुमुल डेयरी सूरत और तापी जिले से दूध एकत्रित करती है और यह गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ (जीसीएमएमएफ) से जुड़ी सहकारी संस्था है, जो अमूल ब्रांड के तहत डेयरी उत्पादों का विपणन और निर्यात करता है।

पशुपालकों की आर्थिक उन्नति के प्रणेता

दीपकभाई द्वारा किए जाने वाले सफल कृत्रिम गर्भाधान से किसानों को सीधा आर्थिक फायदा होता है। कृत्रिम गर्भाधान में 80 फीसदी सफलता दर का अर्थ यह है कि उनके द्वारा किए गए हर 100 पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान में से 80 पशु गर्भधारण करते हैं। इस सफलता के कारण दुग्ध उत्पादन बढ़ता है, पशुपालकों की लागत कम होती है और उनकी आय में वृद्धि होती है।

कार्यक्षेत्र में बढ़ी पशुओं की दुग्ध उत्पादकता

डॉ. पी.आर. पांडे द्वारा दीपक पटेल पर लिखित पुस्तक के अनुसार कृत्रिम गर्भाधान में दीपक पटेल की सफलता उनके कार्यक्षेत्र (महुवा तहसील) में पशुओं की दुग्ध उत्पादकता के आंकड़ों में भी परिलक्षित होती है। देश में एक संकर गाय (क्रॉस बीड) औसतन प्रतिदिन 7.4 लीटर दूध देती है। गुजरात में एक संकर गाय औसतन प्रतिदिन 8.05 लीटर दूध देती है, लेकिन सूरत जिले की महुवा तहसील में एक संकर गाय प्रतिदिन 11.3 लीटर दूध देती है। कृत्रिम गर्भाधान के जरिए उच्च नस्ल वाला पशुधन ज्यादा दूध देता है और इससे पशुपालकों की आय भी बढ़ती है। यह दीपक पटेल की कुशलता और समर्पण ही है, जिसके कारण सूरत जिले की महुवा तहसील के हजारों पशुपालकों की गायें अधिक दूध देती हैं, जिससे उन पशुपालकों की आय में इजाफा हुआ है। दीपक पटेल की उम्र अभी 63 साल है। अपने ज्ञान और कौशल का लाभ आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने अपने दामाद को इस क्षेत्र में काम करने के लिए प्रशिक्षित किया है। उनके दामाद भी अब कृत्रिम गर्भाधान का काम करते हैं और उनके बताए मार्ग पर चल रहे हैं।

उनके जीवन की कहानी किताब और डॉक्यूमेंट्री फिल्म में संजोई गई

डॉ. पी.आर. पांडे और शाश्वत अध्वर्यु ने दीपक पटेल के जीवन पर अंग्रेजी भाषा में 'द मिरेकल बॉय – दीपक पटेल' नामक किताब लिखी है। इसके अलावा, कृत्रिम गर्भाधान के काम से जुड़े तकनीशियनों को प्रेरणा देने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) ने दीपक पटेल के कार्य को दर्शाने के लिए 'सफल बीजदान' नामक एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई है।

केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने भी पशुधन विकास के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए उन्हें सम्मानित किया है, जो उनके कार्य के राष्ट्रीय महत्व को दर्शाता है।

भारत दूध उत्पादन के क्षेत्र में दुनिया के अग्रणी देशों में से एक है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में गुजरात डेयरी क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा है। पूरे विश्व में दूध उत्पादन के क्षेत्र में भारत शीर्ष स्थान पर है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में गुजरात डेयरी उद्योग के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा है, तथा पशु सुधार के लिए पशुपालन विभाग महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

रेल पटरी पार करने की प्रवृत्ति के विरुद्ध रेलवे सुरक्षा बल का जागरूकता अभियान

रेलवे ट्रैक के आसपास रहने वाले निवासियों द्वारा अनधिकृत रूप से पार करने की बढ़ती घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से वडोदरा मंडल के रेल सुरक्षा बल द्वारा व्यापक जन-जागरूकता चलाया जा रहा है।

पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल के जनसंपर्क अधिकारी श्री अनुभव सक्सेना द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार इस अभियान के अंतर्गत रेलवे लाइन के आसपास रहने वाले स्थानीय निवासियों को रेल पटरी को अनधिकृत रूप से पार न करने के बारे में जागरूक किया जा रहा है। उनसे अनुरोध किया जा रहा है कि रेलवे ट्रैक पार करते समय केवल अधिकृत समपार फाटक (लेवल

क्रॉसिंग) अथवा निर्धारित फुट ओवर ब्रिज/अंडरपास का ही उपयोग करें।

श्री सक्सेना ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति रेल पटरी को अवैध रूप से पार करते पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध रेल अधिनियम, 1989 की धारा 147 के अंतर्गत मामला दर्ज कर विधि अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। फरवरी 2026 के दौरान रेलवे सुरक्षा बल, वडोदरा मंडल द्वारा कुल 871 व्यक्तियों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए और उनसे कुल 13,000/- का जुर्माना वसूल किया गया।

वडोदरा मंडल सभी से अपील करता है कि रेल की पार न करें, यह जानलेवा भी हो सकता है।

पश्चिम रेलवे बांद्रा टर्मिनस और आज़मगढ़ के बीच चलाएगी होली सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन

पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा तथा होली त्योहार के दौरान उनकी यात्रा मांग को ध्यान में रखते हुए बांद्रा टर्मिनस और आज़मगढ़ के बीच विशेष किराये पर एक सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस ट्रेन का विवरण निम्नानुसार है:

ट्रेन संख्या 05184 बांद्रा टर्मिनस–आज़मगढ़ स्पेशल 09 एवं 16 मार्च, 2026 को बांद्रा टर्मिनस से 10:45 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन 20:10 बजे आज़मगढ़ पहुँचेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 05183 आज़मगढ़–बांद्रा टर्मिनस स्पेशल 07 एवं 14 मार्च, 2026 को आज़मगढ़ से 23:15 बजे प्रस्थान करेगी और सोमवार को 08:10 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुँचेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, सूरत, वडोदरा, रतलाम, नागदा, कोटा, गंगापुर सिटी, बयाना, ईदगाह आगरा, टूंडला, गोविंदपुरी, प्रयागराज जं., प्रयागराज रामबाग, ज्ञानपुर रोड, बनारस, वाराणसी, औड़िहार, दुल्लहपुर, मऊ एवं मोहम्मदाबाद स्टेशनों पर ठहरेगी।

इस ट्रेन में एसी 3-टियर (इकोनॉमी), स्लीपर श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी के सामान्य कोच होंगे।

ट्रेन संख्या 05184 की बुकिंग 04.03.2026 से सभी पीआरएस काउंटरों तथा आईआरसीटीसी वेबसाइट पर शुरू होगी। ट्रेनों के ठहराव, संरचना एवं समय की विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

पश्चिम रेलवे पर सेवा संकल्प प्रस्ताव का आयोजन

पश्चिम रेलवे द्वारा सोमवार, 02 मार्च, 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित 'सेवा संकल्प' प्रस्ताव के अनुपालन में 'सेवा संकल्प' का पालन किया। इस प्रस्ताव का वाचन किया गया तथा सार्वजनिक सेवा, ईमानदारी, पारदर्शिता एवं आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में जवाबदेही के प्रति प्रतिबद्धता की गंभीर पुष्टि करते हुए इसे अंगीकृत किया गया।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, पश्चिम रेलवे मुख्यालय कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें महाप्रबंधक श्री प्रदीप कुमार ने मुख्यालय में प्रमुख विभागाध्यक्षों (PHoDs) के साथ तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंडल रेल प्रबंधकों (DRMs) एवं मुख्य कारखाना प्रबंधकों (CWMs) के साथ 'सेवा संकल्प प्रस्ताव' का संकल्प

दिलाया। बैठक के उपरांत प्रस्ताव के सिद्धांतों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा क्षेत्रीय स्तर पर लागू किए जाने वाले ठोस कार्यों की पहचान के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई।

इसी प्रकार के आयोजन संबंधित प्रमुख विभागाध्यक्षों (PHoDs), मंडल रेल प्रबंधकों (DRMs), मुख्य कारखाना प्रबंधकों (CWMs) एवं जगजीवन राम अस्पताल के चिकित्सा निदेशक के नेतृत्व में मंडलों तथा उत्पादन इकाइयों/कारखाने में भी आयोजित किए गए। सभी कार्यालयों में अधिकारियों की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए 'सेवा संकल्प' की शपथ दिलाई गई। 'सेवा संकल्प' के महत्व एवं उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए नागरिकों के कल्याण के प्रति समर्पण, नैतिक आचरण तथा उत्तरदायी प्रशासन पर विशेष बल दिया गया।

अहमदाबाद मंडल का शानदार प्रदर्शन: रिकॉर्ड ₹690 करोड़ का राजस्व,पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व में 11.10% की उल्लेखनीय वृद्धि

पश्चिम रेलवे का अहमदाबाद मंडल यात्रियों को सुरक्षित, सुगम एवं बेहतर सेवाएँ प्रदान करने तथा राजस्व वृद्धि के प्रति निरंतर प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में, फरवरी 2026 के दौरान मंडल ने यात्री एवं माल राजस्व, टिकट जांच, गैर-भाड़ा राजस्व (NFR) तथा व्यवसाय विकास के क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। मंडल ने न केवल राजस्व में वृद्धि दर्ज की है, बल्कि माल लदान और यात्री सुविधाओं के क्षेत्र में भी पिछले वर्ष की तुलना में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की है।

कुल राजस्व प्रदर्शन

- कुल आयः फरवरी 2026 में 690 करोड़ का कुल राजस्व अर्जित किया गया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 11.10% अधिक है।
- यात्री राजस्वः 158.02 करोड़ अर्जित किए गए (15.77% की वृद्धि)।
- माल राजस्वः 514.68 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ (10.53% की वृद्धि)।
- टिकट जांचः टिकट जांच अभियान के माध्यम से 2.75 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ (11.79% की वृद्धि)।
- अन्य स्रोतः अन्य विविध स्रोतों से 14.50 करोड़ की आय अर्जित की गई।

माल लदान में ऐतिहासिक उपलब्धि

- वैगन लदानः प्रतिदिन औसतन 2902.74 वैगन लोड किए गए, जो पिछले वर्ष से 7.93% अधिक हैं।
- माल ढुलाईः औसतन 3.92 मिलियन टन प्रतिदिन माल ढुलाई दर्ज की गई (14.70% की वृद्धि)।
- नमक लदानः नमक का लदान औसतन 392.82 वैगन प्रतिदिन रहा

(42.71% की भारी वृद्धि)।

- कंटेनर एवं फर्टिलाइज़रः कंटेनर लदान में 6.36% और फर्टिलाइज़र लदान में 33.47% की वृद्धि दर्ज की गई।
- नया कीर्तिमानः गांधीधाम क्षेत्र में एक ही दिन में 15 लॉन्ग हॉल मालगाड़ियों का परिचालन कर नया रिकॉर्ड स्थापित किया गया।

गैर-भाड़ा राजस्व (NFR) एवं नवाचार

- लक्ष्य से अधिक प्राप्तिः वार्षिक लक्ष्य 13 करोड़ को पार करते हुए 13.18 करोड़ की अब तक की सर्वाधिक गैर-भाड़ा आय अर्जित की गई।
- पार्किंग राजस्वः पार्किंग से 3.12 करोड़ की आय हुई, जो पिछले वर्ष से 17% अधिक है।
- नवाचारः भीमासर में औद्योगिक नमक के लदान हेतु स्टेनलेस स्टील कंटेनर का उपयोग शुरू किया गया, जो टिकाऊ माल प्रबंधन की दिशा में एक नया मानक है।

यात्री सेवाएँ एवं डिजिटल प्रगति

- वंदे भारत एक्सप्रेसः 16 फरवरी 2026 से असारवा-उदयपुर सिटी वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन प्रारंभ हुआ।
- होली स्पेशलः होली पर्व पर विशेष ट्रेनों की 30 ट्रिप संचालित की गईं, जिनसे 0.47 लाख यात्रियों को लाभ हुआ और 5.12 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ।
- डिजिटल टिकटिंगः डिजिटल माध्यमों को बढ़ावा देते हुए PRS में 23.81% और UTS में 34.45% लेनदेन डिजिटल तरीके से संपन्न हुए।

अवसंरचना एवं परिचालन दक्षता

- क्षमता विस्तारः गांधीधाम–आदिपुर खंड पर चौथी लाइन (Quadrupling) का सफलतापूर्वक कमीशनिंग किया गया।
- आधुनिक प्रबंधनः सांतलपुर में आधुनिक 'क्रू मैनेजमेंट सिस्टम' (CMS) का शुभारंभ हुआ।
- परिचालनः DFC डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर प्रतिदिन औसतन 96.86 ट्रेनें चलाई गईं, जो पिछले वर्ष से 18.83% अधिक है।

स्वच्छता एवं प्रवर्तन

- टिकट जांचः विशेष जांच अभियानों के दौरान 3,801 अनियमित यात्रा के मामले पकड़े गए और 26.57 लाख का जुर्माना वसूला गया।
- स्वच्छताः एंटी-लिटरिंग अभियान के तहत 1,120 मामलों में दंडात्मक कार्रवाई की गई।

फरवरी 2026 में अहमदाबाद मंडल का यह प्रदर्शन दर्शाता है कि राजस्व सृजन, माल लदान, डिजिटल प्रगति एवं परिचालन क्षमता जैसे सभी प्रमुख क्षेत्रों में मंडल निरंतर उत्कृष्टता की ओर अग्रसर है।

होली पर्व के दौरान यात्री भीड़ प्रबंधन हेतु व्यापक व्यवस्थाएँ: उन्नत भीड़ नियंत्रण उपायों से सुगम एवं सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित

अहमदाबाद मंडल से 3 लाख से अधिक यात्रियों ने किया सफर

होली पर्व के अवसर पर बढ़ी हुई यात्री भीड़ को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए पश्चिम रेलवे द्वारा व्यापक एवं सुव्यवस्थित व्यवस्थाएँ की गईं। सभी विभागों के मध्य सुदृढ़ समन्वय स्थापित करते हुए यह सुनिश्चित किया गया कि अपने गृह नगरों की ओर यात्रा करने वाले यात्रियों को सुरक्षित, सुगम एवं निर्बाध यात्रा सुविधा प्राप्त हो।

पश्चिम रेलवे ने होली पर्व के दौरान बढ़ी हुई यात्री भीड़ को ध्यान में रखते हुए फरवरी के अंतिम सप्ताह तथा मार्च माह में अपने स्टेशनों से 308 विशेष ट्रेनों के फेरे संचालित करने की घोषणा की है। इसी क्रम में 21 फरवरी से 02 मार्च, 2026 के दौरान पश्चिम रेलवे ने गोरखपुर, बनारस, दानापुर, समस्तीपुर, दरभंगा, भगत की कोठी (जोधपुर), हरिद्वार, रक्सौल, हजरत निजामुद्दीन, दिल्ली सहित अन्य महत्वपूर्ण स्टेशनों के लिए कुल 266 विशेष ट्रेनों का संचालन किया। ये विशेष ट्रेनें उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान एवं गुजरात जैसे प्रमुख राज्यों को जोड़ते हुए यात्रियों की अतिरिक्त मांग को पूरा करने हेतु चलाई गईं। 27 फरवरी से 02 मार्च, 2026 की अवधि के दौरान पश्चिम रेलवे द्वारा 27 लाख से अधिक यात्रियों को उनके गंतव्य तक सुरक्षित एवं सुगम यात्रा सुविधा प्रदान की गई। अहमदाबाद मंडल

के अंतर्गत अहमदाबाद, साबरमती, असारवा, गांधीधाम एवं भुज स्टेशनों से 27, 28 फरवरी एवं 01 मार्च, 2026 को संचालित विशेष ट्रेनों के माध्यम से 3 लाख से अधिक यात्रियों ने यात्रा की।

स्टेशनवार यात्री संख्या इस प्रकार रही –

- अहमदाबाद से लगभग 1.55 लाख यात्री
- साबरमती से 70 हजार यात्री
- असारवा से 30 हजार यात्री
- गांधीधाम से 30 हजार यात्री
- भुज से 15.5 हजार यात्री
- भीड़ प्रबंधन हेतु प्रभावी कदम

होली पर्व के दौरान यात्रियों की सुविधा एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित विशेष उपाय लागू किए गए –

- विशेष ट्रेनों के संबंध में निरंतर उद्घोषणाएँ कर यात्रियों में भ्रम की स्थिति से बचाव किया गया।
- इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड पर ट्रेनों की अद्यतन जानकारी प्रदर्शित की गई।
- रेलवे कर्मचारियों द्वारा यात्रियों को मार्गदर्शन एवं सहायता प्रदान की गई।
- एटीवीएम एवं रेलवन ऐप के माध्यम से टिकट लेने हेतु जागरूकता अभियान चलाया गया।
- मोबाइल यूटीएस सुविधा के माध्यम से कतार में प्रतीक्षारत यात्रियों को टिकट उपलब्ध कराए गए।
- अतिरिक्त आरक्षण काउंटर, एटीवीएम एवं हैंडहेल्ड टिकटिंग टर्मिनल की व्यवस्था की गई।
- प्रमुख स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया बनाकर यात्री आवागमन को सुव्यवस्थित किया गया।
- होल्डिंग एरिया में पेयजल, बैठने की व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक सुविधाएँ सुनिश्चित की गईं।
- विशेष ट्रेनों की जानकारी प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक रूप से प्रसारित की गई।
- परिचालन आवश्यकताओं के अनुरूप ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई।
- प्रमुख स्टेशनों एवं ट्रेनों में रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) तथा टिकट जांच कर्मचारियों की पर्याप्त तैनाती की गई।
- संवेदनशील स्टेशनों पर सीसीटीवी के माध्यम से वास्तविक समय में निगरानी की गई।
- विशेष ट्रेनों की समयपालन सुनिश्चित करने हेतु निरंतर मॉनिटरिंग की गई।
- फुटओवर ब्रिज, प्लेटफॉर्म, प्रवेश/निकास द्वार एवं ट्रेनों में सुरक्षित चढ़ने-उतरने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई।
- पश्चिम रेलवे अपने नेटवर्क पर यात्री आवागमन की सतत निगरानी कर रहा है तथा होली पर्व के दौरान यात्रियों को सुरक्षित, आरामदायक एवं सुविधाजनक यात्रा प्रदान करने के लिए अतिरिक्त विशेष ट्रेनों के संचालन एवं आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता हेतु पूर्णतः प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने नागरिकों को रंग उमंग के होली-धुलंडी पर्व पर शुभकामनाएँ दीं

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के सभी नागरिकों को रंग-उमंग के उत्सव होली-धुलंडी पर्व की शुभकामनाएँ दी हैं। उन्होंने शुभकामनाएँ व्यक्त की हैं कि यह उत्सव जन-जन के जीवन को खुशी, समृद्धि एवं उल्लास के रंगों से तर-ब-तर कर दे।

उन्होंने कहा कि होली का यह पर्व असत्य पर सत्य की विजय का पर्व है। यह त्योहार सबके जीवन में राग-द्वेष भूल कर एक-दूसरे से स्नेह से मिलने तथा सामाजिक समरसता का संदेश देता है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने रंगोत्सव पर्व पर सभी नागरिकों को प्रेषित किए गए अपने संदेश में यह अनुरोध भी किया कि सभी साथ मिलकर इस रंगोत्सव को इस प्रकार मनाएँ कि पर्यावरण का भी जतन हो।

रोमानिया के मिलीसौटी शहर के महापौर गुजरात की यात्रा पर, राज्य के स्मार्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर का जायजा लिया

महापौर ने अहमदाबाद महानगर पालिका तथा शहरी विकास एवं शहरी गृह निर्माण विभाग का दौरा कर अधिकारियों के साथ संवाद किया

गांधीनगर : यूरोपीय देश रोमानिया के मिलीसौटी टाउन के महापौर वासिले कारारे तथा उनकी पत्नी दो दिन की गुजरात यात्रा पर पधारे हैं। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने अहमदाबाद महानगर पालिका तथा राज्य के शहरी विकास एवं शहरी गृह निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ई-गवर्नेंस, शहरी विकास परियोजनाओं, नागरिक केन्द्रिय सेवाओं तथा औद्योगिक विकास के विषय में विचार-विमर्श किया।

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् (आईसीसीआर) द्वारा आयोजित इस यात्रा में श्री कारारे देश के विभिन्न राज्यों की यात्रा कर रहे हैं। गुजरात में उन्होंने अहमदाबाद की महापौर श्रीमती प्रतिभाबेन जैन तथा मनपा आयुक्त श्री बंछानिधि पाणि सहित वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भेंट कर विकास परियोजनाओं, ई-गवर्नेंस, रिवरफ्रंट डेवलपमेंट, अर्बन ट्रांसपोर्ट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट तथा शहरी विकास से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों की जानकारी प्राप्त की। इस बीच उन्होंने अहमदाबाद में इंटीग्रेटेड तथा कंट्रोल सेंटर का भी दौरा किया।

मिलीसौटी के महापौर ने अहमदाबाद के अलावा गांधीनगर में शहरी विकास एवं शहरी गृह निर्माण विभाग के प्रधान सचिव श्री एम. थेन्नारसन, नगर पालिका

प्रशासन आयुक्त सुश्री रेम्या मोहन तथा गुजरात शहरी विकास निगम के अपर मुख्य कार्यवाहक अधिकारी से भेंट की। इस दौरान उन्हें राज्य में शहरी विकास क्षेत्र में चल रही विभिन्न आइकॉनिक परियोजनाओं, ई-गवर्नेंस तथा राज्य सरकार के विजन के बारे में मार्गदर्शित किया गया। श्री कारारे ने मिलीसौटी शहर के लिए रिवरफ्रंट प्रोजेक्ट के विकास में योगदान देने के विषय में राज्य के अधिकारियों के साथ चर्चा की।

चर्चा के दौरान उन्हें बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, धोलेरा हाईवे, सरदार वल्लभभाई पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ड्रीम सिटी सूरत तथा शहर में विभिन्न शहरी विकास परियोजनाओं से सृजित रोजगार के अवसरों के बारे में बताया गया। उन्होंने इस चर्चा में मिलीसौटी में स्मार्ट सिटी के निर्माण के बारे में जानकारी भी प्रस्तुत की और राज्य में गिफ्ट सिटी, साबरमती रिवरफ्रंट तथा धोलेरा के विकास सहित शहरी विकास के लिए हुए कार्यों की प्रशंसा की। गुजरात की अपनी इस यात्रा के दौरान उन्होंने गिफ्ट सिटी का भी दौरा किया।

भारत तथा रोमानिया के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान अधिक सुदृढ़ बनाने एवं दोनों देशों में विद्यमान निवेश के अवसरों को प्रोत्साहन देने के लिए उनकी यह यात्रा महत्वपूर्ण है। उन्होंने रिवरफ्रंट विकास, स्मार्ट सिटी के विकास में एआई तथा डिजिटल प्रणालियों, अर्बन ट्रांसपोर्ट एवं ई-गवर्नेंस क्षेत्र में मौजूद अवसरों की चर्चा कर राज्य के अर्बन इकोसिस्टम, इन्फ्रास्ट्रक्चर व शहरी विकास की परियोजनाओं के विषय में सकारात्मक प्रतिभाव दिया।

मिडिल ईस्ट तनाव की आंच सूरत तक, कोयले के दामों में उछाल से टेक्सटाइल उद्योग पर बढ़ा लागत का दबाव

सूरत। खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव का असर अब हजारों किलोमीटर दूर बसे भारत के प्रमुख टेक्सटाइल हब सूरत पर साफ दिखाई देने लगा है। ईरान और इज़राइल के बीच जारी टकराव, तथा इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका की भूमिका से वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। इस अस्थिरता का सीधा प्रभाव इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया से आयात होने वाले कोयले की कीमतों पर पड़ा है, जिसका बोझ अब सूरत की डाइंग-प्रिंटिंग मिलों और प्रोसेसिंग हाउसों को उठाना पड़ रहा है। हाल ही में आयातित कोयले के दामों में करीब 15 प्रतिशत तक वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे उद्योग जगत में चिंता गहरा गई है।

उद्योग सूत्रों के अनुसार, सूरत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कोयला एक प्रमुख ईंधन स्रोत है, विशेष रूप से डाइंग और प्रोसेसिंग इकाइयों के लिए। एक औसत मिल में प्रतिदिन 40 से 60 टन तक कोयले की खपत होती है। ऐसे में प्रति टन कीमत में मामूली वृद्धि भी कुल उत्पादन लागत पर भारी असर डालती है। पिछले सप्ताह ट्रांसपोर्टेशन चार्ज में अचानक बढ़ोतरी ने उद्योग की परेशानी और बढ़ा दी। शनिवार को 5 डॉलर प्रति टन और उसके बाद सोमवार को 3 डॉलर प्रति टन की अतिरिक्त वृद्धि की गई। भारतीय मुद्रा में यह बढ़ोतरी लगभग 720 रुपये प्रति टन बैठती है, जो बड़े पैमाने पर खपत करने वाली इकाइयों के लिए उल्लेखनीय अतिरिक्त बोझ है।

व्यापारिक संगठनों का कहना है कि कोयले की आपूर्ति मुख्य रूप से इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया से होती है, जहां प्रत्यक्ष रूप से युद्ध जैसी कोई स्थिति नहीं है। इसके बावजूद वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अस्थिरता, समुद्री मार्गों की अनिश्चितता और बीमा व

लॉजिस्टिक्स लागत में वृद्धि का हवाला देकर डिस्ट्रीब्यूटर्स कीमतों में बढ़ोतरी कर रहे हैं। उद्योग से जुड़े कई संचालकों का आरोप है कि वर्तमान परिस्थिति का लाभ उठाकर कृत्रिम रूप से भाव बढ़ाए जा रहे हैं, जिससे स्थानीय इकाइयों पर अनावश्यक दबाव बन रहा है।

साउथ गुजरात टेक्सटाइल प्रोसेसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष जीतूभाई वखारिया ने कहा कि खाड़ी देशों में तनाव शुरू होते ही खास गुणवत्ता वाले कोयले की कीमतों में तेजी की सूचना मिलने लगी थी। उनका मानना है कि यदि अंतरराष्ट्रीय हालात जल्द सामान्य नहीं हुए, तो आने वाले दिनों में और वृद्धि संभव है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि उद्योग की टिकाऊ कार्यप्रणाली बनाए रखने के लिए लागत का पुनर्मूल्यांकन करना पड़ेगा।

कोयले की कीमतों में उछाल ऐसे समय आया है जब टेक्सटाइल उद्योग पहले ही वैश्विक मांग में उतार-चढ़ाव, निर्यात बाजार की अनिश्चितता और घरेलू प्रतिस्पर्धा जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है। सूरत की पहचान देश के सबसे बड़े सिंथेटिक फैब्रिक और ड्रेस मटेरियल उत्पादन केंद्र के रूप में है। यहां हजारों छोटी-बड़ी इकाइयां प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाखों लोगों को रोजगार देती हैं। उत्पादन लागत में वृद्धि का असर केवल मिल मालिकों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह श्रमिकों, सप्लायर्स और अंततः उपभोक्ताओं तक पहुंचता है।

डाइंग और प्रिंटिंग उद्योग से जुड़े संचालकों ने संकेत दिए हैं कि यदि कोयले और परिवहन लागत में इसी प्रकार वृद्धि जारी रही, तो धूलेटी के बाद प्रोसेसिंग चार्ज में बढ़ोतरी की जा सकती है। इसका सीधा असर ग्रे कपड़े से तैयार फैब्रिक तक की लागत पर पड़ेगा। यदि प्रोसेसिंग दरें बढ़ती हैं, तो थोक और खुदरा बाजार में तैयार कपड़ों की कीमतों में भी उछाल आ सकता है। उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि लागत का यह दबाव अंततः उपभोक्ता बाजार तक पहुंचेगा और महंगाई की एक नई परत जोड़ सकता है।

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए साउथ गुजरात टेक्सटाइल प्रोसेसर्स एसोसिएशन द्वारा अगले सप्ताह जनरल बोर्ड मीटिंग बुलाने की तैयारी की जा रही है। इस बैठक में कोयले की वर्तमान कीमतों, ट्रांसपोर्टेशन लागत, संभावित रेट रिवीजन और सरकार से अपेक्षित सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। उद्योग प्रतिनिधि यह भी विचार कर सकते हैं कि क्या वैकल्पिक ईंधन स्रोतों या ऊर्जा दक्ष तकनीकों की ओर आंशिक रूप से रुख किया जा सकता है, ताकि भविष्य में इस प्रकार के वैश्विक झटकों का प्रभाव कम किया जा सके।

विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक बाजार आज परस्पर जुड़ा हुआ है, जहां किसी एक क्षेत्र में तनाव का असर दूर-दराज के औद्योगिक केंद्रों तक महसूस किया जाता है। सूरत का टेक्सटाइल उद्योग इसका ताजा उदाहरण है। यदि कच्चे माल और ईंधन की लागत पर नियंत्रण नहीं हुआ, तो निर्यात प्रतिस्पर्धा भी प्रभावित हो सकती है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय खरीदार मूल्य संवेदनशील होते हैं। ऐसे में उद्योग और सरकार के बीच समन्वय तथा दीर्घकालिक ऊर्जा रणनीति की आवश्यकता और अधिक बढ़ जाती है।

फिलहाल सूरत का टेक्सटाइल उद्योग हालात पर नजर बनाए हुए है। उम्मीद की जा रही है कि अंतरराष्ट्रीय तनाव में कमी आने पर बाजार स्थिर होगा और कोयले की कीमतों में राहत मिलेगी। लेकिन जब तक स्थिति स्पष्ट नहीं होती, तब तक उत्पादन लागत का बढ़ता दबाव उद्योग के लिए चुनौती बना रहेगा, और इसका प्रभाव पूरे वस्त्र बाजार पर देखने को मिल सकता है।

वडोदरा मंडल में 'सेवा संकल्प' के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु उच्चस्तरीय बैठक

केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित 'सेवा संकल्प' के प्रभावी क्रियान्वयन के क्रम में वडोदरा मंडल में सोमवार, 02 मार्च 2026 को वडोदरा मंडल के मंडल कार्यालय में मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय बैठक का आयोजन किया गया।

पश्चिम रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी श्री अनुभव सक्सेना द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार, बैठक की अध्यक्षता मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके द्वारा की गई, जिसमें मंडल के सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

अपने अध्यक्षीय संबोधन में मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके ने कहा कि भारतीय रेल केवल एक परिवहन सेवा नहीं, बल्कि देश के करोड़ों नागरिकों के दैनिक जीवन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक व्यवस्था है। यात्रियों एवं आम नागरिकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं को अधिक प्रभावी, समयबद्ध, संवेदनशील तथा परिणामोन्मुख बनाना प्रत्येक रेल

अधिकारी एवं कर्मचारी की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से सेवा संकल्प की भावना को दैनिक कार्यप्रणाली में आत्मसात करते हुए उत्कृष्ट एवं जनोन्मुख सेवाएं प्रदान करने का आह्वान किया।

इस अवसर पर मंडल कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी श्री तेजराम मीना ने सेवा संकल्प का वाचन किया। अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने लोक सेवा के प्रति समर्पण, तथा ईमानदारी, पारदर्शिता तथा जवाबदेही के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने का संकल्प लिया।

कार्यक्रम के पश्चात संकल्प के सिद्धांतों को व्यवहार में उतारने तथा मंडल स्तर पर ठोस कार्यवाही सुनिश्चित करने के उपायों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।

वडोदरा में रेल पटरियों पर जानलेवा लापरवाही के खिलाफ बड़ा अभियान, आरपीएफ की सख्ती और जागरूकता से 871 मामलों में कार्रवाई

वडोदरा। तेजी से शहरीकरण और आबादी के विस्तार के बीच रेलवे ट्रैक के आसपास अनधिकृत रूप से आवाजाही की बढ़ती प्रवृत्ति ने रेलवे प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल में हाल के महीनों में रेल पटरियों को शॉर्टकट के रूप में इस्तेमाल करने की घटनाओं में वृद्धि देखी गई है, जिसके चलते रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने व्यापक स्तर पर जन-जागरूकता और सख्त प्रवर्तन अभियान शुरू किया है। यह अभियान केवल नियमों की जानकारी देने तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों की मानसिकता बदलने और उन्हें संभावित खतरों के प्रति सचेत करने की दिशा में भी गंभीर प्रयास कर रहा है।

रेलवे ट्रैक के आसपास कई बस्तियां, कॉलोनियां और अनौपचारिक रास्ते विकसित हो गए हैं, जहां रहने वाले लोग दैनिक आवागमन के लिए पटरियों को पार करना आसान समझते हैं। कई मामलों में लोग अधिकृत समपार फाटक, फुट ओवर ब्रिज या अंडरपास की बजाय सीधे ट्रैक पार कर लेते हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इसी जोखिम को कम करने के

उद्देश्य से पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल ने रेलवे सुरक्षा बल की टीमों को संवेदनशील इलाकों में तैनात किया है। आरपीएफ के जवान न केवल निगरानी कर रहे हैं, बल्कि स्थानीय नागरिकों से सीधे संवाद कर उन्हें समझा भी रहे हैं कि कुछ मिनटों की बचत के लिए अपनी जान जोखिम में डालना समझदारी नहीं है।

पश्चिम रेलवे, वडोदरा मंडल के जनसंपर्क अधिकारी अनुभव सक्सेना द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, अभियान के तहत रेलवे लाइन के निकट रहने वाले परिवारों, दुकानदारों, विद्यार्थियों और दैनिक मजदूरी करने वाले लोगों से संपर्क कर उन्हें रेल सुरक्षा नियमों की जानकारी दी जा रही है। पर्चे वितरित किए जा रहे हैं, लाउडस्पीकर के माध्यम से घोषणाएं की जा रही हैं और सामुदायिक बैठकों का आयोजन कर जागरूकता संदेश दिया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि कई लोग यह समझते हैं कि यदि ट्रेन दूर दिख रही है तो वे सुरक्षित रूप से ट्रैक पार कर सकते हैं, लेकिन तेज गति से आती ट्रेनों का अनुमान लगाना अक्सर गलत साबित होता है। कई दुर्घटनाएं इसी गलत आकलन के कारण होती हैं।

रेलवे प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि रेल परिसर में अनधिकृत प्रवेश या पटरियों को अवैध रूप से पार करना कानूनन अपराध है। रेल अधिनियम, 1989 की धारा 147 के अंतर्गत ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर जुर्माना और अन्य दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है। फरवरी 2026 के दौरान वडोदरा मंडल में इस प्रावधान के तहत कुल 871 व्यक्तियों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए और उनसे कुल 13,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया। अधिकारियों का कहना है कि यह आंकड़ा केवल एक महीने का है, जो इस समस्या की गंभीरता को दर्शाता है। हालांकि जुर्माने की राशि अपेक्षाकृत कम हो सकती है, लेकिन इसका उद्देश्य लोगों को चेतावनी देना और नियमों के प्रति सजग करना है।

अभियान का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि आरपीएफ केवल दंडात्मक कार्रवाई पर निर्भर नहीं है, बल्कि रोकथाम और शिक्षा पर भी बराबर जोर दे रहा है। स्कूलों और कॉलेजों में विशेष सत्र आयोजित किए जा रहे हैं, जहां छात्रों को रेल सुरक्षा के बारे में बताया जा रहा है। बच्चों को यह समझाया जा रहा है कि मोबाइल फोन, हेडफोन या बातचीत में व्यस्त होकर ट्रैक पार करना अत्यंत खतरनाक है। कई मामलों में देखा गया है कि लोग कानों में ईयरफोन लगाकर संगीत सुनते हुए पटरियां पार करते हैं और उन्हें आती ट्रेन की आवाज सुनाई नहीं देती, जिससे गंभीर हादसे हो जाते हैं।

रेलवे अधिकारियों ने यह भी बताया कि वडोदरा मंडल एक व्यस्त रेल मार्ग है, जहां यात्री और मालगाड़ियों की आवाजाही लगातार बनी रहती है। ट्रेनों की गति अधिक होने के कारण चालक के लिए अचानक ट्रैक पर आए व्यक्ति को देखकर तुरंत ट्रेन रोक पाना संभव नहीं होता। ऐसे में छोटी सी लापरवाही भी जानलेवा साबित हो सकती है। प्रशासन ने यह दोहराया है कि अधिकृत समपार फाटक, फुट ओवर ब्रिज और अंडरपास यात्रियों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं और उनका उपयोग करना ही जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य है।

अभियान के दौरान स्थानीय समुदायों के प्रतिनिधियों और समाजसेवी संगठनों को भी जोड़ा जा रहा है, ताकि संदेश अधिक प्रभावी ढंग से लोगों तक पहुंचे। रेलवे ट्रैक के पास रहने वाले लोगों से विशेष रूप से अपील की जा रही है कि वे अपने बच्चों को भी पटरियों के पास खेलने या अनधिकृत रूप से पार करने से रोकें। कई दुर्घटनाएं बच्चों के खेल-खेल में ट्रैक पर जाने से भी होती हैं, जिन्हें थोड़ी सी सतर्कता से रोका जा सकता है।

पश्चिम रेलवे द्वारा होली त्योहार की भीड़ को संभालने के लिए व्यापक व्यवस्थाएँ

पश्चिम रेलवे द्वारा उन्नत भीड़ प्रबंधन उपायों के साथ सुगम एवं सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित

पश्चिम रेलवे द्वारा होली त्योहार के दौरान यात्रियों की भारी भीड़ के प्रभावी प्रबंधन हेतु व्यापक व्यवस्थाएँ की गई हैं। पश्चिम रेलवे द्वारा इस त्योहार पर अपने गृह नगरों की ओर यात्रा कर रहे रेल यात्रियों के लिए सभी विभागों के बीच समन्वित और कुशल तालमेल के माध्यम से सुगम, सुरक्षित एवं निर्बाध यात्रा सुनिश्चित की गई है।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, होली त्योहार के अवसर पर यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए पश्चिम रेलवे द्वारा फरवरी के अंतिम सप्ताह से मार्च माह तक अपने स्टेशनों से स्पेशल ट्रेनों के 308 फेरे चलाने की घोषणा की गई है। तदनुसार, 21 फरवरी से 02 मार्च, 2026 तक पश्चिम रेलवे द्वारा द्वारा गोरखपुर, बनारस, दानापुर, समस्तीपुर, दरभंगा, भगत की कोठी (जोधपुर), हरिद्वार, रक्सौल, हजरत निजामुद्दीन, दिल्ली सहित अन्य महत्वपूर्ण स्टेशनों के लिए 266 स्पेशल ट्रेनें परिचालित की गईं। इन ट्रेनों के माध्यम से उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान तथा गुजरात जैसे प्रमुख राज्यों को कवर करते हुए यात्रियों की मांग को पूरा किया गया। 27 फरवरी से 02 मार्च, 2026 की अवधि के दौरान जोन द्वारा 27 लाख से अधिक यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुँचाया गया।

भीड़ प्रबंधन हेतु उठाये गये प्रभावी कदम

त्योहार के दौरान बढ़ी हुई यात्री भीड़ के सुव्यवस्थित प्रबंधन के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए:

- स्पेशल ट्रेनों के संबंध में यात्रियों में किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति से बचने हेतु नियमित घोषणाएँ की गईं।
- स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड के माध्यम से ट्रेनों की जानकारी प्रदर्शित की गई।
- रेल कर्मचारियों द्वारा स्टेशनों पर यात्रियों को समुचित मार्गदर्शन एवं सहायता प्रदान की गई।
- यात्रियों को एटीवीएम तथा रेलवन ऐप के माध्यम से टिकट खरीदने के लिए प्रेरित करने हेतु प्रचार-प्रसार अभियान चलाए गए।
- कतार में प्रतीक्षा कर रहे यात्रियों को टिकट जारी करने हेतु स्टेशनों पर मोबाइल यूटीएस टिकटिंग सुविधा उपलब्ध कराई गई।
- त्वरित टिकट निर्गमन सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त बुकिंग काउंटर, एटीवीएम तथा हैंड-हेल्ड टिकटिंग टर्मिनल की व्यवस्था की गई।
- महत्वपूर्ण स्टेशनों पर यात्री आवागमन को विनियमित करने एवं भीड़ नियंत्रण के लिए होल्डिंग एरिया बनाए गए।
- होल्डिंग एरिया में यात्रियों की सुविधा हेतु पेयजल, बैठने की व्यवस्था एवं अन्य मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराई गईं।
- स्पेशल ट्रेनों की जानकारी का व्यापक प्रचार-प्रसार प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया के माध्यम से किया गया।
- ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों द्वारा उभरती परिचालन आवश्यकताओं के अनुरूप त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की गई।
- प्रमुख स्टेशनों एवं ट्रेनों में पर्याप्त रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) तथा टिकट जांच स्टाफ की तैनाती की गई।
- संवेदनशील स्टेशनों पर यात्री आवागमन की रीयल-टाइम निगरानी हेतु ड्रोन कैमरा एवं सीसीटीवी सर्विलांस का उपयोग किया गया।
- स्पेशल ट्रेनों के समयबद्ध परिचालन को सुनिश्चित करने हेतु सतत निगरानी की गई।
- यात्रियों के सुरक्षित चढ़ने एवं उतरने की व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए प्रभावी भीड़ प्रबंधन किया गया, जिसके तहत फुट ओवर ब्रिज, प्लेटफॉर्म, प्रवेश/निकास द्वार तथा ट्रेनों के भीतर आरपीएफ कर्मियों की तैनाती की गई।

पश्चिम रेलवे अपने संपूर्ण नेटवर्क पर यात्री आवागमन की निरंतर एवं गहन निगरानी कर रही है तथा होली त्योहार के दौरान यात्रियों को सुरक्षित, आरामदायक एवं सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित करने हेतु आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त स्पेशल ट्रेन सेवाएँ चलाने और आवश्यक संसाधनों की तैनाती के लिए पूर्णतः तत्पर है।

सूरत में शोक की लहर: राजस्थान युवा संघ के अध्यक्ष विक्रमसिंह शेखावत का हृदयाघात से आकस्मिक निधन

सूरत। शहर के प्रवासी राजस्थानियों के बीच अत्यंत सम्मानित और सक्रिय सामाजिक व्यक्तित्व, राजस्थान युवा संघ के अध्यक्ष विक्रमसिंह शेखावत का मंगलवार, 3 मार्च की दोपहर अचानक हृदयाघात से निधन हो गया। उनके आकस्मिक निधन की खबर जैसे ही शहर में फैली, समाज में गहरा शोक छा गया। अस्पताल परिसर में देखते ही देखते शुभचिंतकों, समाजजनों, व्यापारिक साथियों और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों की भीड़ उमड़ पड़ी। हर व्यक्ति के चेहरे पर अविश्वास और पीड़ा साफ दिखाई दे रही थी, मानो किसी ने समाज की मजबूत कड़ी को अचानक छीन लिया हो। बताया जाता है कि वे पिछले कुछ दिनों से व्यस्त कार्यक्रमों में लगातार सक्रिय थे। सोमवार रात्रि को ही होली के अवसर पर आयोजित पारंपरिक तीन दिवसीय फागोत्सव का समापन उनके नेतृत्व में सफलतापूर्वक हुआ था। कार्यक्रम में उन्होंने पूरे उत्साह और ऊर्जा के साथ समाजजनों का मार्गदर्शन किया था। किसी को अंदेशा भी नहीं था कि अगले ही दिन वे इस दुनिया को अलविदा कह देंगे। उनका जाना केवल एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं, बल्कि समाज के एक प्रेरक नेतृत्व का अचानक समाप्त हो जाना है।

अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को नई सिविल अस्पताल लाया गया, जहां हजारों लोगों ने नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। राजनीतिक, सामाजिक और औद्योगिक क्षेत्र की अनेक हस्तियां वहां उपस्थित रहीं। वातावरण में गहरा सन्नाटा और शोक की अनुभूति थी। समाज की महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों ने उन्हें याद करते हुए कहा कि वे केवल संगठन के अध्यक्ष नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के सुख-दुख में साथ खड़े रहने वाले संरक्षक थे। अंतिम श्रद्धांजलि के बाद उनके पार्थिव शरीर को सूरत एयरपोर्ट ले जाया गया, जहां से हवाई मार्ग द्वारा उनके पैतृक गांव राजस्थान के लिए रवाना किया गया, ताकि वहां पूरे रीति-रिवाज के साथ अंतिम संस्कार किया जा सके।

विक्रमसिंह शेखावत केवल एक संगठनात्मक पदाधिकारी भर नहीं थे, बल्कि वे समाज को एक सूत्र में पिरोने वाले सशक्त नेतृत्वकर्ता के रूप में जाने जाते थे। उनके नेतृत्व में राजस्थान युवा संघ ने कई सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों का सफल आयोजन किया। प्रवासी राजस्थानियों के बीच आपसी सहयोग, भाईचारा और सांस्कृतिक पहचान को सशक्त बनाए रखने में उनका योगदान उल्लेखनीय रहा। युवाओं को समाज सेवा के लिए प्रेरित करना, जरूरतमंद परिवारों की सहायता करना और सामूहिक आयोजनों को नई ऊर्जा देना उनकी कार्यशैली की पहचान थी।

वे लघु उद्योग भारती सूरत जिला इकाई के अध्यक्ष के रूप में भी सक्रिय थे और व्यापारिक जगत में उनकी अलग पहचान थी। उद्योग और समाज सेवा के बीच संतुलन स्थापित करते हुए उन्होंने अनेक उद्यमियों को मार्गदर्शन दिया। छोटे और मध्यम उद्योगों से जुड़े लोगों के हितों के लिए वे निरंतर प्रयासरत रहते थे। उनके नेतृत्व में कई जागरूकता कार्यक्रम, परामर्श बैठकें और सामाजिक सहयोग गतिविधियां संचालित हुईं, जिससे सूरत में बसे प्रवासी समाज को एक नई दिशा मिली।

समाज के वरिष्ठजनों का कहना है कि शेखावत में नेतृत्व की स्वाभाविक क्षमता थी। वे निर्णय लेने में दृढ़, व्यवहार में विनम्र और कार्य के प्रति अत्यंत प्रतिबद्ध थे। किसी भी आयोजन में वे स्वयं उपस्थित रहकर हर छोटी-बड़ी व्यवस्था पर ध्यान देते थे। यही कारण था कि समाज के युवा उन्हें अपना मार्गदर्शक मानते थे। वे मानते थे कि संगठित समाज ही मजबूत समाज होता है, और इसी सोच के साथ उन्होंने विभिन्न वर्गों को एक मंच पर लाने का निरंतर प्रयास किया। उनके निधन से सूरत में बसे राजस्थान समाज को गहरा आघात पहुंचा है। सामाजिक एकता और सेवा भावना के जो बीज उन्होंने बोए, वे आने वाले समय में भी समाज को प्रेरित करते रहेंगे। अनेक संगठनों ने शोक संदेश जारी कर उनके योगदान को स्मरण किया और परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। समाजजनों ने कहा कि उनका जीवन समर्पण, कर्तव्यनिष्ठा और सकारात्मक नेतृत्व का उदाहरण था।

सोना वायदा 4149 रुपये और चांदी वायदा 10805 रुपये लुढ़का: क्रूड ऑयल वायदा में 584 रुपये का ऊछाल

मुंबई: देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 50370.32 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 8949.42 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 41420.9 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 1804.88 करोड़ रुपये का हुआ।

कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 6795.15 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना अप्रैल वायदा 161995 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 162999 रुपये और नीचे में 159649 रुपये पर पहुंचकर, 166074 रुपये के पिछले बंद के सामने 4149 रुपये या 2.5 फीसदी गिरकर 161925 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर पहुंचा। गोल्ड-गिनी मार्च वायदा 3512 रुपये या 2.59 फीसदी गिरकर 132261 रुपये प्रति 8 ग्राम हुआ। गोल्ड-पेटल मार्च वायदा 424 रुपये या 2.48 फीसदी गिरकर 16651 रुपये प्रति 1 ग्राम हुआ। सोना-मिनी मार्च वायदा सत्र के आरंभ में 159500 रुपये के भाव पर खूलकर, 159609 रुपये के दिन के उच्च और 156048 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 4304 रुपये या 2.63 फीसदी गिरकर 159255 रुपये प्रति 10 ग्राम हुआ। गोल्ड-टेन मार्च वायदा प्रति 10 ग्राम सत्र के आरंभ में 165206 रुपये के भाव पर खूलकर, 166500 रुपये के दिन के उच्च और 157067 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 167092 रुपये के पिछले बंद के सामने 4260 रुपये या 2.55 फीसदी गिरकर 162832 रुपये प्रति 10 ग्राम हुआ।

चांदी के वायदाओं में चांदी मार्च वायदा 259320 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 259320 रुपये और नीचे में 259320 रुपये पर पहुंचकर, 270125 रुपये के पिछले बंद के सामने 10805 रुपये या 4 फीसदी घटकर 259320 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा

कमोडिटी वायदाओं में 8949.42 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 41420.9 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवर : सोना-चांदी के वायदाओं में 6795.15 करोड़ रुपये का हुआ कारोबार

था। इनके अलावा चांदी-मिनी अप्रैल वायदा 18684 रुपये या 6.55 फीसदी लुढ़ककर 266442 रुपये प्रति किलो बोला गया। जबकि चांदी-माइक्रो अप्रैल वायदा 18855 रुपये या 6.61 फीसदी घटकर 266382 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था।

मेटल वर्ग में 779.48 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा मार्च वायदा 21.05 रुपये या 1.73 फीसदी गिरकर 1193.75 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा। जबकि जस्ता मार्च वायदा 1.6 रुपये या 0.49 फीसदी गिरकर 325.75 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा। इसके सामने एल्यूमीनियम मार्च वायदा 6.45 रुपये या 2.02 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 325.55 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि सीसा मार्च वायदा 65 पैसे या 0.34 फीसदी घटकर 189.05 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था। इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 1002.45 करोड़ रुपये के सौदे किए।

एमसीएक्स क्रूड ऑयल मार्च वायदा 6650 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 7081 रुपये और नीचे में 6650 रुपये पर पहुंचकर, 584 रुपये या 8.99 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 7081 रुपये प्रति बैरल पर आ गया। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी मार्च वायदा 584 रुपये या 8.99 फीसदी की बढ़त के साथ 7081 रुपये प्रति बैरल के भाव पर कारोबार कर रहा था। इनके अलावा नैचुरल गैस मार्च वायदा 278 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 288 रुपये और नीचे में 277.9 रुपये पर पहुंचकर, 271.7 रुपये के पिछले बंद के सामने 15.3 रुपये या 5.63 फीसदी बढ़कर 287 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि नैचुरल गैस-मिनी मार्च वायदा 14.9 रुपये या 5.48 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 286.9 रुपये प्रति एमएमबीटीयू पर आ गया।

कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 6037.91 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 757.23 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 571.44 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 138.50 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 2.33 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 67.21 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 181.42 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 817.95 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 9698 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 77657 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 27185 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 397234 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 53035 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 7283 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 17544 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 65500 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 22276 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 27825 लोट के स्तर पर था।

कमोडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल मार्च 7000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 306 रुपये की बढ़त के साथ 552.4 रुपये हुआ।

सोना मार्च 200000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 13 रुपये की गिरावट के साथ 519 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी मार्च 300000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 4212.5 रुपये की गिरावट के साथ 11047 रुपये हुआ। तांबा मार्च 1200 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 7.3 रुपये की गिरावट के साथ 36 रुपये हुआ।

पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल मार्च 7000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 279.5 रुपये की गिरावट के साथ 469 रुपये हुआ।

सोना मार्च 150000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 838.5 रुपये की बढ़त के साथ 1700 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी मार्च 200000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 1569 रुपये की बढ़त के साथ 2900 रुपये हुआ। तांबा मार्च 1200 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 11.3 रुपये की बढ़त के साथ 39.12 रुपये हुआ।